

माह-ए-रमजान

इफ्तार (मंगलवार): 05:58
सेहरी (बुधवार): 04:43

SHARE

सेंसेक्स : 74,115.17
निफ्टी : 22,460.30

SARAFARAS

सोना : 8,230
चांदी : 108.00

(नोट : सोना 22 केरट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

राहुल ने की वोट लिस्ट पर चर्चा कराने की मांग

NEW DELHI : सोमवार को लोकसभा में नेता विपक्ष नराहुल गांधी ने सदन में मतदाता सूची में अनियमितता का मुद्दा उठाया और कहा कि देशभर से इसकी शिकायतें मिल रही हैं। गैर एनडीए शासित राज्यों से यह मुद्दा उठ रहा है। राहुल ने विशेष रूप से महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। साथ ही उन्होंने मांग की कि पूरा विपक्ष चाहता है कि सदन में वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में शून्य काल की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती, लेकिन पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो। विपक्षी राज्यों और पूरे देश से मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है।

मप्र में सड़क हादसे में 9 लोगों की गई जान

SEEDHI : मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार-सोमवार की दरमियानी रात हुए भीषण सड़क हादसे में नौ लोगों की जान चली गई। यहां पनी पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ़्तार ट्रैक्टर और जीप के बीच सीधी भिड़त हो गई। आठ लोगों की मौके पर ही मौत। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 13 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में सात को गंभीर हालत में रीवा मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया है। मृतकों में पांच महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं।

एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

NEW DELHI : मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-119 को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। 8 घंटे 37 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट में 19 क्रू मेंबर समेत 322 यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने बताया कि फ्लाइट के वॉशरूम में एक नोट मिला, जिसमें बम की धमकी दी गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रास्ते से ही विमान को वापस मुंबई लाने का फैसला किया गया। विमान 10:25 बजे मुंबई पहुंचा। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-119 मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से रात 1:43 बजे न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी। फिनहॉल सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं।

सुपरिणाम विगत 10 वर्षों में बचाए गए लोगों के 30 हजार करोड़ रुपये

केंद्र सरकार के जन औषधि केंद्रों ने जनता का किया बड़ा कल्याण

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में जनहित के कार्यों में तेजी लाने पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके परिणाम भी धीरे-धीरे दिख रहे हैं। चंद दिन पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि देशभर में केंद्र सरकार और 25 हजार जन औषधि केंद्र खोलेंगे, ताकि लोगों को विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सस्ते दवाओं पर दवाएं उपलब्ध हो सकें। स्वास्थ्य की देखरेख के लिए उनके खर्चे में कुछ कमी आ सके। इस बीच यह महत्वपूर्ण खबर सामने आई कि पिछले 10 सालों में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जनता के कितने पैसों से अब तक बचे हैं। सस्ती और किकायती दवाओं के लिए देश का जन औषधि मॉडल अब जमीनी स्तर पर हजारों करोड़ों रुपये की बचत के रूप में सामने आया है। बीते 10 सालों में जन औषधि दवाओं से मरीजों के 30 हजार करोड़ रुपये बचे हैं। लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक सप्ताह तक अभियान शुरू कर दिया है।

PHOTON NEWS RANCHI :

सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र सत्र के 10वें दिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गरमा गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सभी भाजपा विधायक इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर रबीनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा कि राज्य में कुछ दिनों से हत्या के मामले काफी अधिक बढ़ गए हैं। उन्होंने झामुमो के स्लोगन पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लोग हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देते हैं। लेकिन, उन्हें तो लागता है हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत है। उन्होंने रांची के कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हुई फायरिंग, चान्ही में हुए साधुओं की हत्या और हजारीबाग के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या का मुद्दा उठाया। बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था को राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा बताते हुए इस पर चर्चा की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर खड़े किए कई गंभीर सवाल झामुमो के स्लोगन पर कसा तंज, कहा- हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत है



डीजीपी की कार्यशैली पर बिफरे सीपी सिंह

सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया। राज्य के डीजीपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया डीजीपी कहते हैं कि राज्य में हो रही बढ़ी-बढ़ी

घटनाओं की योजनाएं जेल से बनती हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या जेल झारखंड से बाहर है। जेल इसी राजधानी में है तो फिर क्यों इसका उद्देश्य नहीं किया जाता। सीपी सिंह ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब की मांग की है।



जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की तैयारी

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में आदिवासी हित में जनजातीय सलाहकार परिषद के कार्यरत होने, अनुसूचित जातीय सलाहकार परिषद का गठन नहीं किए जाने और इसके लिए सरकार के स्तर से किए जाने

वाले प्रयासों को लेकर सवाल पूछा। राज्य में 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी के लिए टीएससी की तर्ज पर अनुसूचित जातीय सलाहकार परिषद के गठन पर कहा कि झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद नियमावली 2008 अधिसूचित किया गया है।

दर्दनाक : गढ़वा में गोदरमाना के मुख्य बाजार में हुई घटना

पटाखे की दुकान में लगी आग दो बच्चों सहित पांच की गई जान

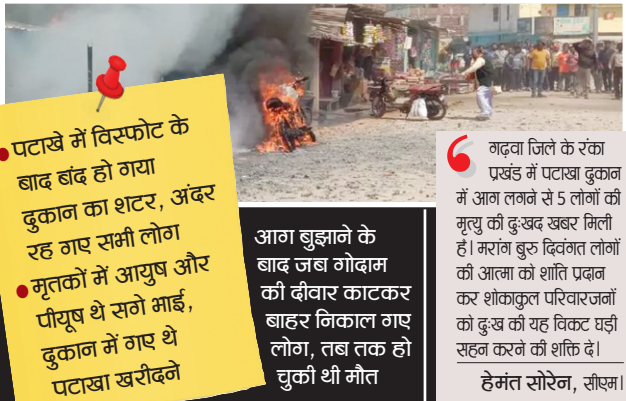
PHOTON NEWS GARHWA :

सोमवार को गढ़वा जिले में रंका प्रखंड के गोदरमाना के मुख्य बाजार में एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना कुश कुमार गुप्ता की दुकान में हुई। दुकान में दिन में करीब 11:30 बजे आग लगी। इसमें दुकानदार कुश कुमार गुप्ता समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुश कुमार किराने और पटाखे की दुकान चलाते थे। पटाखे की दुकान के पीछे 2 गोदाम हैं। अचानक एक पटाखा फूटा और देखते ही देखते पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग तेजी से फैलती चली गई। पटाखे में विस्फोट के बाद दुकान का शटर बंद हो गया और सभी 5 लोग उसी में बंद हो गए। आग बुझाए जाने के बाद जब सभी को गोदाम की दीवार को काटकर बाहर निकाला गया, तो

अचानक एक पटाखा फूटा और देखते ही देखते फैल गई आग

दम घुटने से मौत

ग्रामीणों ने बताया कि दुकान में जब आग लगी, तो किसी को मालूम नहीं था कि अंदर 5 लोग फंसे हुए हैं। बाद में पता चला, तो गोदाम के पीछे की दीवार तोड़कर सभी 5 लोगों को निकाला गया। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि सभी की मौत दम घुटने से हुई है। आग लगने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से दमकल वाहन आया। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर आधे घंटे के भीतर काबू पा लिया।



आग बुझाने के बाद जब गोदाम की दीवार काटकर बाहर निकाला गए लोग, तब तक हो चुकी थी मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पटाखा दुकान में आग लगते ही अफरातफरी का माहौल बन गया। आसपास के सभी लोग जान बचाकर भागने लगे। चारों तरफ बम-पटाखे फटने की आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते आग इतनी भयावह हो गई कि दुकान के पास खड़ी एक बाइक भी उसकी चपेट में आ गई।

सभी की मौत हो चुकी थी। मृतकों में गुप्ता (45), अजित कुमार केसरी, सुशीला केरकेट्टा (18), आयुष कुमार केसरी (10) और पीयूष कुमार केसरी (8) के रूप में हुई

राशन दुकान के बाहर पटाखे बेच रहा था दुकानदार

गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि राशन दुकान के बाहर दुकानदार पटाखा भी बेच रहा था। दो बच्चे पटाखे खरीदने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी दौरान पटाखे में आग लग गई और वहां अफरातफरी मच गई। दुकानदार दोनों बच्चे समेत अग्नित केशरी और सुशीला केरकेट्टा को लेकर दुकान के पास ही एक खाली गोदाम में घुस गया और अंदर से शटर लगा दिया। इसी दौरान आग का धुआं अंदर घुसने लगा। बाहर जब लोगों को पता चला कि दुकानदार कुछ लोगों के साथ अंदर बंद है तो दीवार काटकर उन्हें बहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। लोग पांचों को सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज स्थित एक अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने पांचों को मृत घोषित कर दिया।

है। गोदरमाना के रहने वाले आयुष और पीयूष दोनों सगे भाई थे।



सुप्रीम कोर्ट का विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश

RANCHI : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश सुशांत भुलिया और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने रजनीश कुमार पांडेय बनाम भारत सरकार के मामले में यह निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

आशिक या पूर्ण रूप से नि:शक्त बच्चों को विशेष बच्चों के नाम से जाना जाता है। इन बच्चों को पढ़ाई के दौरान आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया था कि वे इन विशेष बच्चों के लिए अलग से शिक्षकों का पद स्वीकृत कर शिक्षकों को नियुक्त करें। प्राइमरी स्कूल में विशेष बच्चों के लिए शिक्षक व छात्र का अनुपात 1:10 और मिडिल स्कूल में 1:15 निर्धारित है। मामले को सुनवाई के दौरान सभी राज्यों ने अंदाजित को विशेष बच्चों की संख्या की जानकारी दी है।

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया स्वीकार, 3 अपराधी जेल से चला रहे गैंग



PHOTON NEWS RANCHI :

सोमवार को एक ओर विधानसभा में राज्य में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर हंगामा हुआ, तो दूसरी ओर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि जेल में बंद अपराधी जेल से ही अपना गैंग चला रहे हैं। उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, ये तीन अपराधी हैं, जो जेल से अपना गैंग चला रहे हैं। वे वरचुंअल नंबर क्रिएट कर काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने एटीएस एसपी को निर्देश दिया है कि बीएनएस की धारा 111 के तहत काम करें। यह धारा संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस को काम करने का पावर देती है। डीजीपी ने कहा कि इस धारा के तहत अमन साव गिरोह के 30 लोगों पर एफआईआर की

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की बातचीत

- » विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव पर जल्द कसा जाएगा शिकंजा
- » जोर देकर कहा, 30 अपराधियों पर दर्ज की जा चुकी है एफआईआर
- » बीएनएस की धारा 111 के तहत काम करने का एटीएस एसपी को दिया निर्देश

गई है। जल्द ही सभी को गिरफ्तारी होगी। सभी हो जेल भेजेंगे। उन्होंने इस बात को खुल कर कहा कि झारखंड में जितने क्राइम हो रहे हैं, वो जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं। वहीं से कराए भी जा रहे हैं। हम काफी प्रयास कर रहे हैं कि जेल से हो रही इन गतिविधियों को रोके।

रांची में फायरिंग मामले का जल्द होगा खुलासा

शुक्रवार को रांची में कोयला व्यवसायी पर फायरिंग मामले को लेकर डीजीपी ने कहा कि रांची फायरिंग मामले में सभी अपराधियों की पहचान हो चुकी है। हम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे। हजारीबाग एनटीपीसी डीजीएम गौरव कुमार की हत्या की गूथी सुलझाने में जुटी पुलिस के अभी भी हाथ खाली हैं। हालांकि डीजीपी अनुराग गुप्ता का मानना है कि जल्द ही इस मामले में पुलिस अपराधी तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की गूथी सुलझाने के लिए पुलिस के द्वारा

एसआईटी का गठन किया गया है और जगह-जगह छापेमारी की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि यह हत्या क्यों हुई है, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। उन्होंने कहा कि रांची में हुई फायरिंग की घटना का उद्देश्य जल्द ही पुलिस के द्वारा कर लिया जाएगा। इस मामले में सभी अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है। जल्द ही दो से तीन दिनों के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

सीएस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला सुरक्षा की दृष्टि से अब टोयोटा लैंड क्रूजर में चलेंगे मुख्यमंत्री

PHOTON NEWS RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुरक्षा की दृष्टि से अब टोयोटा लैंड क्रूजर 300 जीआर स्पेडर्स में चलेंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासी पदसंग समिति की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। समिति में विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना विकास विभाग के सचिव सदस्य हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में उपलब्ध वाहन जो रद्द करने के योग्य हैं, उन्हें रद्द करके नीलामी की जाए। साथ ही नीलामी की राशि को कोषागार में जमा किया जाए। इससे पहले हुई



•पूर्व में उपलब्ध वाहन जो रद्द करने के योग्य हैं उनकी होगी नीलामी

प्रशासी पदसंग समिति की बैठक में झारखंड भवन नई दिल्ली में सीएम के कारकेड में टोयोटा इनोवा हाईक्रोस टॉप मॉडल खरीदने की स्वीकृति दी गई थी।

BRIEF NEWS

लातेहार में पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार



LATEHAR : जिले के मनिका थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी विनोद परहिया उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादी पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में आठ से अधिक मामले दर्ज हैं। सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उग्रवादी विनोद उर्फ अर्जुन मनिका थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए भ्रमणशील है। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई और नक्सली की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस को देखकर नक्सली भागने लगा, परंतु पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली क्षेत्र में दहशत बनाकर रखा हुआ था। लोगों को फोन कर लेवी की मांग करना इसका मुख्य धंधा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी को लातेहार पुलिस ने पूर्व में भी एक बार गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन मेल से बाहर आने के बाद यह फिर से संगठन में शामिल होकर हिंसक घटनाओं को अंजाम देने लगा था। उन्होंने बताया कि इसकी गिरफ्तारी से पीएलएफआई संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है।

नुक्कड़ नाटक में बताए अफ्रीम के दुष्प्रभाव



KHUNTI : जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को खुंटी प्रखंड के सिम्बुकेल सहित अन्य क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवैध अफ्रीम की खेती के दुष्प्रभावों से आमजनों और किसानों को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को अवैध खेती को छोड़कर वैकल्पिक और लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि अवैध अफ्रीम की खेती न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह समाज और स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। किसानों को समझाया गया कि वे अफ्रीम की खेती को छोड़कर ड्रैन फ्रूट, टमाटर, बैंगन, मूंग इत्यादि जैसी लाभकारी फसलों की खेती करें, जिससे उनकी आजीविका भी सुरक्षित रहे और समाज में सकारात्मक बदलाव आए। इस दौरान किसानों को जागरूक करने के लिए पम्पलेट का भी वितरण किया गया।

याद की गई सावित्रीबाई फुले



JAMSHEDPUR : कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक-4 में सावित्रीबाई फुले सेवा दल, जमशेदपुर ने सोमवार को महिला सशक्तीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं प्रखर विचारक सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में विनीता भगत, अंजलि कुमारी, प्रिया कुमारी, खुशी कुमारी, विकास मुखी, राजेश भगत, रुपेश कुमार ठाकुर, धीरज मुखी, अवधेश कुमार, विनय रजक, अजीत कुमार भगत, रोहन अभिषेक कुमार आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन महेश भगत ने किया।

बच्चों को दिया गया इम्युनिटी बूस्टर का डोज



एवं विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य महेश्वर महतो ने भगवान धन्वंतरि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुवर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, याददाश्त सुधारने और मानसिक विकास में सहायक होती है। यह दवा माह में एक बार पुन्य नक्षत्र के दिन पिलाता जाा। वाटिका प्रमुख अंजु कुमारी ने बताया यह दवा जन्म से बारह वर्ष तक के बच्चों के लिए है। जिन्हें वर्ष में 12 डोज दिया जाना है। उन्होंने अभिभावकों के बीच इस आयुर्वेदिक दवा से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताया।

सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत

तीनों युवक रामगढ़ थाना क्षेत्र के कणहारा गांव के निवासी, अलग-अलग हादसे के हुए शिकार

AGENCY DUMKA :

जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई। पहली सड़क दुर्घटना में मामा-भांजा की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर मौसरे भाई की शादी से लौट रहे बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

पहली घटना जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के फुलजोरी गांव के पास घटी। जहां ऑटो रिक्शा और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतकों की पहचान सचिन मोसाद और ढालू संतरा के रूप में हुई है। जबकि घायल अरविंद संतरा को इलाज के लिए फूलो ज्ञानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक रामगढ़ थाना क्षेत्र के



अस्पताल में रखे गए शव

● फोटोन न्यूज

थाना क्षेत्र के लकड़ापहाड़ी गांव का निवासी था। वह अपने मौसरे भाई के शादी में शामिल होकर दुमका आ रहा था। घर लौटने के क्रम में उसकी बाइक को पीछे से एक ट्रक ने ठोकर मार दी। इससे वह सड़क पर गिर गया। लेकिन ट्रक ने उसकी कमर के नीचे कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बोकारो में महिला डॉक्टर का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

BOKARO : बीजीएच के डीएनबी गर्ल्स हॉस्टल में महिला डॉक्टर आर्या झा (29) का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएम) के डीएनबी गर्ल्स हॉस्टल में डॉक्टर का फंदे से झूलता शव बरामद हुआ। घटना रविवार देर रात की है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने घटना की पुष्टि की है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 4 थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका ने कुछ दिन पहले ही बीजीएच में डीएनबी फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। और वह गाइनेकोलॉजी में डीएनबी कर रही थी। मृतका की रूम पार्टनर इयूटी खत्म कर वापस लौटी तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। काफी



अस्पताल के पास लगी गीड़

खटखटाने के बाद दरवाजा न खुलने पर उसने हॉस्टल के अन्य डॉक्टरों को सूचना दी। दरवाजा धक्का देकर खोला गया तो महिला डॉक्टर का शव फंदे से लटका पाया। मौजूद डॉक्टर ने बताया कि महिला सुबह की कैजुअल्टी में इयूटी कर चुकी थी। मौत के कारणों का पुलिस पता लगा रही है।

होली में हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन की रहेगी कड़ी नजर

AGENCY LOHARDAGA :

होली पर्व पर हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर होगी। इसे लेकर उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि होली का त्यौहार सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से मनायें। अगर बच्चे व युवा किसी पर रंग फेंक देते हैं तो उन्हें एक अभिभावक की तरह समझाएँ। किसी प्रकार की असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें। होली का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सके इसके लिए दण्डाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बारीकी से असमाजिक तत्वों पर नजर रखी



बैठक में उपस्थित डीसी-एसपी व अन्य पदाधिकारी

● फोटोन न्यूज

जा रही है। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां ने कहा कि होली में त्योहार की मूल भावना का ख्याल रखा जाय। किसी को भी आहत ना करें। भारत देश में होली काफी उत्साह तरीके से मनाया जाता रहा है। आप जब भी होली खेलें तो आपसी भाईचारा और गंगा-जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश करें। उन्होंने बताया कि जिला में त्यौहार को मनाने के लिए पर्याप्त

पुलिस बल की उपलब्धता है। शांति समिति के लोग होली में अभिभावक की भूमिका में रहें और युवाओं को संयमित रखने के लिए प्रयास करें। जिला में प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। आवश्यक पुलिस बल है, ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी की जाएगी। बैठक में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

यूसिल कर्मी हारुन रशीद का शव बरामद



मृतक की फाइल फोटो

JADUGORA : यूसिल कर्मी हारुन रशीद की रहस्यमय ढंग से मौत के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उसका शव यूसिल के सुरक्षा गाड़ों ने दरवाजा तोड़कर निकाला। शव से दुर्गंध आने की वजह से माना जा रहा है कि शव तीन चार दिन पुराना होगा। जब दरवाजा तोड़ा गया तो शव बेड पर पड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक या अन्य कारणों से मौत हुई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत पर से पर्दा उठ पाएगा। पुलिस शव बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं पर सिपाहियों ने चटकाई लाटियां

RAMGARH : झारखंड के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं पर सिपाहियों ने लाठी चटका दी। कतार में लगे श्रद्धालुओं पर डंडे बरसाती पुलिस का वीडियो भी वायरल हुआ है। रजरप्पा मंदिर प्रांगण में हुई इस वारदात को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार पुटुस ने इस घटना की निंदा की। इस विषय पर धनंजय कुमार पुटुस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में जब भी मुंडन का लगन होता है तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा में लगे जवानों को संयम से काम लेना चाहिए ना कि श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज करना चाहिए। मां

दोनों सिपाही लाइनवलोज

एसपी अजय कुमार ने बताया कि एकादशी को लेकर रजरप्पा में भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। मुंडन का भी मुहूर्त था, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबी कतार है लगी हुई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरे दिन पुलिस के पदाधिकारी और जवान वहां मुस्तैद थे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आया कि श्रद्धालुओं पर दो सिपाहियों ने लाठी चलाई है। जांव के दौरान पता चला कि दोनों जेप के जवान थे और उन्हें मंदिर परिसर में इयूटी पर तैनात किया गया था। उनके इस अनैतिक व्यवहार को लेकर उन्हें लाइनवलोज कर दिया गया है।

छिन्नमस्तिका मंदिर विख्यात मंदिर हैं। यहां झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं।

महिलाओं ने बनाया हर्बल गुलाल



LOHARDAGA : होली का त्योहार रंगभरी एकादशी से शुरू हो गया है। सनातनी एक-दूसरे को गुलाल-अबीर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल के छात्र भी रंगोत्सव के मूड में नजर आ रहे हैं। केमिकल युक्त रंगों से बचने के लिए जेसलपीएस से जुड़ी महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार की हैं। जेसलपीएस की टीम हर्बल रंग से होली खेलने के फायदे बता रहे हैं। हर्बल गुलाल की बिक्री चौक चौराहे पर स्टॉल लगाकर की जा रही है। महिलाओं ने खुद पर्यावरण अनुकूल हर्बल गुलाल तैयार किया है। महिलाएं ही इसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग भी कर रही हैं। पलाश ब्रांड के तहत ग्रामीण महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं।

प्रतिस्पर्धी झारखंड : सतत और समावेशी विकास के लिए साझेदारी पर कॉरपोरेट हस्तियों ने रखे विचार

सीआईआई झारखंड के चेयरमैन बने टाटा मोटर्स के प्लांट हेड सुनील तिवारी



PHOTON NEWS JSR : बिष्टुपुर स्थित होटल अलकोर में सोमवार को सीआईआई, झारखंड काउंसिल की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए टाटा मोटर्स के प्लांट हेड सुनील कुमार तिवारी को चेयरमैन और वैदेही मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलू पारीख को सीआईआई झारखंड स्टेट काउंसिल का वाइस चेयरमैन चुना गया। जमशेदपुर में जन्मे और पले-बढ़े दिलू पारीख ऑटोमोबाइल व्यवसाय से जुड़े हैं। इसी क्रम में प्रतिस्पर्धी झारखंड : सतत और समावेशी विकास के



डीसी अनवरत मित्तल को मेमोर्टो गेंट करते टिनाल्ट के एमडी उज्जल चक्रवर्ती

लिए भागीदारी पर चर्चा हुई, जिसमें झारखंड को भारत के आर्थिक परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने पर कॉरपोरेट हस्तियों ने अपने विचार रखे। जेके सिंह (सचिव-श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार) ने एमएसएमई के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए

खनिजों का स्थानीय स्तर पर हो प्रसंस्करण : रणजोत सिंह

सीआईआई झारखंड स्टेट काउंसिल के निवर्तमान अध्यक्ष और एमडेट जमशेदपुर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रणजोत सिंह ने झारखंड के लिए विकसित भारत के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी औद्योगिक प्रासंगिकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राज्य से निकाले गए खनिजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। उन्होंने दृढ़ता से अपना विश्वास भी व्यक्त किया कि झारखंड अपने समृद्ध संसाधनों और अपार विकास क्षमता को देखते हुए उद्योगों के लिए सबसे अच्छा गंतव्य है। उन्होंने सीआईआई की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिनमें 27 प्रमुख आयोजन, 17 कार्यालयाएं और प्रशिक्षण सत्र, सुरक्षा ऑडिट, सरकारी बातचीत और खेल आयोजन शामिल हैं।

सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिससे उनकी वृद्धि और स्थिरता को सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि उद्योग कार्निवल का मुख्य फोकस 'बाजार तक पहुंच' एमएसएमई के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो सीधे उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता को प्रभावित करती है। उन्होंने 2015 से अनिवार्य सार्वजनिक खरीद नीति के बारे में विस्तार से बताया

और बताया कि कैसे उद्योग कार्निवल खरीद के अवसरों का पता लगाने और एमएसएमई का आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। उन्होंने रक्षा और रेलवे जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी संबोधित किया, गुणवत्ता और आपूर्ति सीमा पर विचार-विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया।

आईटी व ऑटोमोबाइल को बनाना होगा मजबूत : बेहसा

सीआईआई पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष और आरएसबी टांसमिशन (आई) लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुभेद्र बेहरा ने अपने विचार-विमर्श में झारखंड को हरित राज्य बनाया और आईटी और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में इसकी मजबूत क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्थिरता को एकीकृत करने की वकालत की और सरकार से विनिर्माण में प्रक्रिया उन्नयन के लिए योजनाएं शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने भू-राजनीतिक चुनौतियों को भी संबोधित किया, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी पारस्परिक शुल्क के प्रभाव पर प्रकाश डाला और टिकाऊ उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका ध्यान हरित विनिर्माण और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने पर रहा। उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए झारखंड और बंगाल के बीच मजबूत सरकार-उद्योग साझेदारी के साथ-साथ सहयोग पर भी जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने ऊर्जा-कुशल और उन्नत तकनीकों को अपनाने में उद्योगों का समर्थन करने वाले सरकारी प्रायधानों और सब्सिडी को रेखांकित किया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले के विकास के लिए प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समावेशी विकास पर जोर दिया, यह सुनिश्चित किया कि कोई भी

समुदाय पीछे न छूटे और औद्योगिक व सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान किया। मित्तल ने लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, स्थिरता के लिए हरित समाधान अपनाने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

झारखंड के लिए बनना चाहिए मास्टरप्लान : चाणक्य चौधरी

सीआईआई झारखंड स्टेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और टाटा स्टील लिमिटेड के वीपी-कॉरपोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिरता घर से शुरू होती है। उन्होंने खनन प्रक्रियाओं का आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए ओडिशा की यात्रा से प्राप्त अंतर्दृष्टि साझा की। श्रम समावेशिता को संबोधित करते हुए, उन्होंने महिलाओं के लिए नाइट इयूटी की कैबिनेट से मंजूरी का स्वागत किया, सुरक्षा के लिए कॉरपोरेट जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने मात दुलाई और खनिज गलियारों की आवश्यकता पर जोर दिया और एक शक्तिशाली संदेश के साथ समापन किया, उन्होंने कहा कि झारखंड के पास संसाधन हैं; अब, हितधारकों को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। वहीं, सीआईआई झारखंड के निवर्तमान वाइस चेयरमैन और टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ऋतुजित सिन्हा ने नीतिगत मामलों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

समाचार सार

हो भाषा व साहित्य प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत

CHAIBASA : चाईबासा सदर प्रखंड के कमारहातु नवयुवक समिति व टाइटैनिक क्लब गुडसाई द्वारा आयोजित हो भाषा व साहित्य प्रतियोगिता के विजेताओं को मतकमहातु पंचायत की मुखिया जुलियाना देवगम, नीमडीह पंचायत की मुखिया सुमित्रा देवगम व कमारहातु के मुंडा बिरसा देवगम ने पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में मेघराज सिंकू प्रथम, गांधी लागुरी द्वितीय और पाईकराय सिसुई ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं गुलशन गागराई, कस्तूरी सावैया, सरस्वती सावैया, मलिन सिंकू, विशू पूर्ति, रघुनाथ जोको और लखन पिंगुवा को सात्वना पुरस्कार दिया गया।

कोल्हान अधीक्षक नियुक्त करने की मांग

MANOHARPUR : मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने सोमवार को विधानसभा में कोल्हान अधीक्षक नियुक्त करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि कोल्हान अधीक्षक का पद प्रभार में चलने के कारण आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। विधायक के प्रश्नोत्तर में सरकार ने कहा कि उपयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को कोल्हान अधीक्षक के पद पर पदस्थापन की जाती रही है। वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा को इस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

गोलमुरी में निकली श्याम निशान यात्रा

JAMSHEDPUR : फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी पर सोमवार को गोलमुरी में भव्य श्री श्याम (ध्वज) निशान यात्रा गोलमुरी मेन रोड, बजरंग चौक से निकल कर बाजार घूम कर श्री शिव मंदिर गोलमुरी में खाटू श्याम को निशान अर्पित कर समापन हुआ। निशान यात्रा में 251 निशान के साथ श्री श्याम दरबार, डीजे, पुष्प वर्षा, बैड-बाजा, भजनों के साथ, झूमते हुए बाबा को रिझा रहे थे।

प. सिंहभूम में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हुआ समझौता

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम के जिला समाहरणालय में सोमवार को उपयुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की उपस्थिति में, जिला स्वास्थ्य समिति और फिया फाउंडेशन द्वारा संचालित ईडिया हेल्थ एंड क्लाइमेट

रेजिलिएंस फेलोशिप कार्यक्रम के बीच एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसका उद्देश्य जिले की स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, सामुदायिक लचीलापन बढ़ाना और स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचारों को बढ़ावा देना है। समझौते पर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो माझी और फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक जॉनसन टोपनो ने हस्ताक्षर किए।

ग्राम प्रधान के निधन पर जताया शोक

GHATSILA : रघुनाथपुर गांव के ग्राम प्रधान गौरकुण्ड पाल की मौत पर पारंपरिक खशासन व्यवस्था माझी परगना महाल के घाट रेणिल प्रखंड अध्यक्ष सह देश विचार सचिव बाहादुर सोरेन तथा महासचिव सुधीर कुमार सोरेन ने ग्राम प्रधान के परिवार से मिल कर शोक व्यक्त किया।

योजना व कानून की दी गई जानकारी

GHATSILA : स्वाधीना संस्था ने सोमवार को सुंदरनगर स्थित समेकित जन विकास केंद्र में दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर महिला सशक्तीकरण पर चर्चा की गई। रंची से आए वन अधिकार अधिनियम के कार्यक्रम तकनीकी सलाहकार तुषार कुंभकार ने वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया। कार्यशाला में पटमदा प्रखंड के 18 और मुसाबनी प्रखंड के 20 ग्रामीणों ने भाग लिया।

जमशेदपुर पर आधारित पुस्तक लोकार्पित

JAMSHEDPUR : साकची स्थित राजेंद्र विद्यालय में सोमवार को जमशेदपुर आधारित पुस्तक सृजन के आयाम का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पुस्तक के लेखक जयराम सिंह, बिहार एसोसिएशन के महासचिव सीपीएन सिंह व संयुक्त सचिव अमरेश्वर सिन्हा भी मंचस्थ थे। कार्यक्रम का संचालन रामप्रवेश सिंह ने किया।

सीएसआईआर-एनएमएल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का हुआ आयोजन

याद किए गए राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक

PHOTON NEWS JSR : बर्माईस स्थित सीएसआईआर-एनएमएल में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, झारखंड चैप्टर और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीआईटी मेसरा के प्रो. प्रतीम कुमार चट्टराज और जीएसआई झारखंड के असद अहसन रजा भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अभिलाष (एमएनएससी) ने किया। डॉ. संदीप घोष चौधरी, निदेशक, सीएसआईआर-एनएमएल ने स्वागत भाषण दिया और राष्ट्र निर्माण तथा भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में प्रख्यात वैज्ञानिकों के योगदान को याद किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की विरासत पर भी चर्च की। बीआईटी मेसरा के कुलपति और



कार्यक्रम का उद्घाटन करते एनएमएल के निदेशक संदीप घोष चौधरी

और धातु विज्ञान से लेकर स्वच्छ ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं सहित विज्ञान के सभी पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विश्व युद्ध के आरंभ से अब तक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में विश्वस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कठिन प्रयासों का उल्लेख किया। प्रोफेसर चट्टराज ने अपने विषय आधारित व्याख्यान में रसायन विज्ञान, भौतिकी और धातुकर्म के गहन सार को उदाहरणों के माध्यम से समझाया तथा सर सी.वी. रमन के कार्यों और उनकी उपलब्धियों तथा प्रकाश

प्रकीर्णन, रेल प्रकीर्णन और स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भी बताया। उन्होंने सांस्कृतिक विज्ञान और भारत के बाहर भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने की दिशा में सर सीवी रमन द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाया। एए रजा ने झारखंड में महत्वपूर्ण धातुओं की जानकारी दी और लिथियम तथा आर्सेई भंडार दोहन के कई क्षेत्रों में एनएमएल के योगदान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसके बाद महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कार्यक्रम में 135 छात्रों और 75 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन बीआईटी मेसरा के प्रो. अनिमेष घोष के धन्यवाद प्रस्ताव और राष्ट्रगान के साथ हुआ।



JAMSHEDPUR : मानगो में टैंक रोड स्थित पोद्दार भवन में रविवार को पोद्दार वैश्य कल्याण समिति द्वारा पारिवारिक होली मिलन किया गया इसमें महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। सभी ने एक-दूसरे को अबीर लगाकर खुशियां बांटी और होली की बधाई दी। सुरुचि व्यंजनों का स्वाद भी चखा। समिति के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक अध्यक्ष शंकर पोद्दार की मौजूदगी में कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अरुण पोद्दार व संचालन महासचिव श्रीकांत देव ने किया। कार्यक्रम में शिवशंकर प्रसाद देव, रामानुज पोद्दार, भारत पोद्दार, नीज नोगेंद्र पोद्दार, नंदकिशोर पोद्दार आदि भी शामिल थे।

पुलिस ने गोरा गैंग के तीन बदमाशों को भेजा जेल, बना रहे थे हत्या की योजना गुप्त सूचना पर शास्त्रीनगर में छापेमारी कर दबोचे गए अपराधी, कुछ हो गए फरार



पत्रकारों को मामले की जानकारी देते एसएसपी किशोर कौशल

फोटोन न्यूज

बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में शास्त्रीनगर ब्लॉक-2 निवासी इरफान व अफसर खान और बिष्टपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह स्थित एशियन इन होटल के पास रहने वाला सैफ शामिल है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि वे हत्या की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस के छापे के बाद वे अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर सके।

पुलिस ने इन बदमाशों से उन फरार अपराधियों के बारे में भी पूछताछ की, जो छापेमारी के समय मौके से भाग गए थे। अब पुलिस उन फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

टाटा स्टील से विस्थापितों ने रखी सात सूत्री मांग



JAMSHEDPUR : टाटा स्टील के ऑफिस में सोमवार को वार्ता हुई, जिसमें विस्थापितों ने कई मांग रखी। टाटा स्टील, लैंड डिपार्टमेंट के प्रमुख, भूमि प्रबंधन के अमित सिंह के समक्ष विस्थापितों ने जो 7 मांग रखी, उसमें टाटा कंपनी और डिमना डैम के विस्थापितों को विस्थापित प्रमाण पत्र दिया जाए, 1932 खतियान के आधार पर विस्थापितों को चिह्नित कर विस्थापितों को पुनर्वास व मुआवजा दिया जाए। 1996 के सर्वे सेटलमेंट को रद्द किया जाए आदि प्रमुख हैं। अमित सिंह ने कहा कि डिमना डैम विस्थापितों के साथ वार्ता फिर से प्रारंभ कर उन्हें न्याय देने का प्रयास करेंगे।

आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए जमा 65 आय व 47 जन्म प्रमाणपत्र मिले फर्जी

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले के निजी स्कूलों में राईट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन के लिए जमा आवेदन पत्रों की जांच चल रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 112 प्रमाणपत्र फर्जी मिले हैं। इसमें आय प्रमाणपत्र 65, जबकि 47 जन्म प्रमाणपत्र हैं। आवेदन फॉर्म में सलग इन दोनों प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन जांच कराई जा रही है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अभी भी 1200 प्रमाणपत्रों की जांच बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में फर्जी प्रमाणपत्रों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यह संख्या 200 के करीब पहुंच सकती है। जिले के निजी स्कूलों की बात करें तो आरक्षित कोटे की कुल 1504 सीटें हैं। इनमें दाखिले के लिए कुल 3 हजार आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। ऐसे किया फर्जीवाड़ा: निन आय व जन्म प्रमाणपत्रों को फर्जी बताया गया है, उनकी जांच में यह बात सामने आई कि अभिभावकों ने आय प्रमाणपत्र को रकून कर अपनी आय को कम दिखाया है।

जमशेदपुर में अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार

PHOTON NEWS JSR : होली पर्व के मद्देनजर अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सोमवार को उलीडीह ओपी क्षेत्र में एक मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले की उत्पाद विभाग की टीम ने डिमना रेसीडेंसी हाउसिंग सोसाइटी के डुप्लेक्स डी-22 में छापेमारी कर इस अवैध कारोबार का पदाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में स्पिरिट, रंगीन शराब, विभिन्न ब्रांडों के खाली बोतल, ढक्कन, नकली लेबल, सीलिंग कॉर्क, शराब में मिलाए जाने वाले प्लेवरिंग एजेंट (उंशै) सहित भारी मात्रा में शराब जब््त की गई। मौके से कुल 70 पेटा

परसुडीह में मिठाई कारोबारी के घर चोरी पुलिस ने डोंग स्वचॉयड लेकर शुरू की जांच

JAMSHEDPUR : परसुडीह थाना क्षेत्र के शीतला चौक स्थित गौरी भवन के पास रहने वाले मिठाई कारोबारी गोपाल घोष के घर चोरी हुई है। यह घटना तब हुई, जब गोपाल घोष का घर बंद था और वह दूसरे घर में सो रहे थे। उनका बेटा इन दिनों नेपाल घूमने गया है। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों रुपये के गहनों की चोरी कर ली। घटना की जानकारी तब मिली, जब गोपाल घोष सुबह अपने घर पहुंचे और देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी टूटकर खाली पड़ी थी। यह देखकर वह समझ गए कि घर में चोरी हो चुकी है। पुलिस को सूचना देने के बाद, परसुडीह थाना की पुलिस डोंग स्वचॉयड और फिंगर एक्सपर्ट की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घर में विभिन्न जगहों से अंगुली के निशान एकत्रित किए और सदिग्ध वस्तुओं को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कोई अहम जानकारी मिल सकती है। गोपाल घोष ने बताया कि उनका बेटा जब नेपाल से लौटेगा, तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि चोरों ने कितने गहने और अन्य सामान चुराए हैं। उन्होंने बेटे को चोरी की सूचना दे दी है।

सीआईएसएफ के जवान देश के लिए समर्पित : सीएमडी

JADUGORA : यूसिल कंपनी की सुरक्षा में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से सोमवार को 56वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सीआईएसएफ की ओर से बैरक मैदान में मुख्य समारोह हुआ। जवानों ने चारों दिशाओं से दुश्मनों के हमले से बचते हुए विजय कैसे प्राप्त करें, इसे लेकर मार्क ड्रिल किया गया। इसके साथ ही अन्य कई प्रदर्शन कर अपनी ताकत का अहसास कराया। समारोह के मुख्य अतिथि यूसिल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉ. संतोष सतपति ने परेड की सलामी ली व उन्होंने यूसिल की न्यूक्लियर पावर कार्यक्रम की सुरक्षा की बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे सीआईएसएफ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन जवानों की अचूक सुरक्षा को लेकर आने वाले दिनों में देश की संसद भवन में भी सीआईएसएफ की तैनाती की संभावना जताई। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट रॉकी पीएस ने कहा कि 10 मार्च 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई, जहां दो लाख से अधिक जवान 259 संस्थाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। कार्यक्रम में यूसिल के वित्त निदेशक विक्रम केसरी दास, उपमहाप्रबंधक राकेश कुमार, सहायक कमांडेंट अक्षय उगले, इंस्पेक्टर पवन कुमार, इंस्पेक्टर एसके सिंह आदि जवानों व अधिकारियों ने भाग लिया।



प्रदर्शन करते सीआईएसएफ के जवान



बरामद शराब के साथ आबकारी विभाग के पदाधिकारी

फोटोन न्यूज

बरामद अवैध शराब
● स्पिरिट- 140 लीटर
● बोतलबंद शराब- 630 लीटर
● तैयार शराब- 100 लीटर
● तैयार शराब मूल्य- लगभग 15 लाख रुपए।

बरामद की गई। इस मिनी फैक्ट्री के संचालक बालीगुमा के रहने वाले धीरज कुमार सिंह को भारने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जल संकट को निपटाने के लिए सभी मुखिया ने लगाई गुहार



कार्यपालक अभियंता को सगल्या बताते विभिन्न पंचायतों के मुखिया

CHAKRADHARPUR : गर्मी के दस्तक देते ही ग्रामीण क्षेत्र के नदी-नाले सूखने लगे हैं। पंचायतों में जल संकट होना तय है। समय से पहले निपटाने को लेकर सोमवार को प्रखंड के सभी मुखिया, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता नवीन भगत से मिले। उन्होंने समय से पहले चापाकलों की मरम्मत कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना अधिकांश जगहों पर बंकरा साबित हुआ है। अब भी गांवों में योजना अधूरी है। योजना

को पूर्ण कराएं तथा संबंधित संवेदकों को निर्देश दिया जाए कि वह इसे पूर्ण करें। कार्यपालक अभियंता ने आश्वासन दिया कि जल संकट से निपटारा को लेकर विभाग पहले से ही तत्पर है। हेल्ललाइन नंबर भी जारी करेंगे। इस दौरान मुखिया जंगल सिंह गागराई, शांति देवी, मेलानी बोदरा, सैलाई मुंडा, पिंकी जोंको, दया सागर केराई, सोमनाथ रजक, सरिता गागराई, मुखिया प्रतिनिधि मंटू गागराई, गंगाराई गागराई आदि मौजूद थे।

BRIEF NEWS

अभिनेता पवन सिंह आदर्श आचार संहिता के एक मामले में बरी
DEHRI : रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय से सोमवार को भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता पवन सिंह आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी हो गए। बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में दोष मुक्त करार दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी रहे पवन सिंह के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में चार मामला दर्ज हुआ था। सोमवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें एक मामले में बरी कर दिया।

'राजद ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाया'
DEHRI : सोमवार को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बयान जारी कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितैषी होने के दावे को राजनीतिक ढोंग बताते हुए कहा कि राजद केवल अल्पसंख्यकों को गुमराह कर उनका वोट बटोरने की राजनीति करती है लेकिन हकीकत यह है कि 15 वर्षों के शासन में लालू-राबड़ी की सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को सिर्फ ठगा गया। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के वास्तविक हितों की रक्षा हेतु नीतीश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी, उर्दू शिक्षकों की बहाली, मंदरसा शिक्षकों को वेतनमान, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तालिमी मरकज, मरदसों का आधुनिकरण सहित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं धरातल पर उतारा।

नमाज अदा कर लौट रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या
DEHRI : जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में तरावीह की नमाज अदा कर लौट रहे व्यक्ति के सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना रविवार की रात रामगढ़वा थाना के बैरिया पंचायत के आर्यानगर की है। जहां बदमाशों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान 53 वर्षीय शेख नुरेन के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रामगढ़वा थाना पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।स्थानीय लोगो के मुताबिक रविवार रात 9.30 बजे के आसपास बदमाशों ने शेख नुरेन के सीने में गोली मारी और घटना को अंजाम देने के बाद पैदल ही भाग निकले। बदमाशों की संख्या दो बताई जा रही है। गोली लगते ही शेख नुरेन जमीन पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सोमवार को पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया को बताया कि घटना को लेकर रक्सौल डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। प्रथम दृष्टया अपसी दुश्मनी में घटना की बात सामने आ रही है। घटना में दो अपराधी शामिल हैं।

विधानसभा सत्र राज्यकर्मियों के लिए वेतन भत्ता और समूह जीवन बीमा की उठी मांग

अलग-अलग होती है केंद्र व राज्य सरकार की नीति : उद्योग मंत्री

AGENCY PATNA :

बिहार विधानसभा में बजट सत्र के आज सातवें दिन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरुआत की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए। प्रश्नकाल में पहला सवाल करते हुए विधायक अजय सिंह केंद्रीय कर्मियों की भाति राज्यकर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी व अन्य सुविधा देने की मांग की। विधायक अजय सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने जो उत्तर दिया है की राज्य कर्मियों के वेतन भत्ते केंद्रीय कर्मियों के समरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बद्ध नहीं है। मैं इस जवाब को चुनौती देता हूं। विधायक सिंह ने कहा कि मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या बिहार सरकार और राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ जिसमें तय हुआ था कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी देय होगा। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से 25 लाख रुपये करने पर विचार रखती



रंग-गुलाल लगवाने से क्यों होता है परहेज : हरिभूषण ठाकुर



PATNA : बिहार विधानमंडल के परिसर में बजट सत्र के सातवें दिन भाजपा के फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बबौल ने होली में रंग गुलाल और अबीर की बिंदी मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं करने की नसीहत दी है। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बबौल ने कहा है कि होली में रंग-गुलाल और अबीर की बिंदी मुस्लिम समुदाय के लोग ना करें। रंग-गुलाल लगवाने से मुसलमानों को परहेज होता है, तो बिंदी क्यों करते हैं? होली जुम्मे (शुक्रवार) के दिन है, हिंदुओं को होली मनाने दें, अगर रंग से आपति है तो उसे दिन घर से ना निकलें। वैसे भी साल में 52 जुम्मा (शुक्रवार) होता है। एक दिन नहीं ही निकले और बड़ा दिल दिखाएं।

है। विधायक अजय सिंह के प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि केंद्र और राज्य

सरकार की नीति अलग-अलग होती है। राज्य सरकार केंद्रीय कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता देने के लिए

बाध्य नहीं है। मंत्री ने प्रश्नकर्ता से पूछा कि क्या दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं,यह बताइए। स्पीकर ने प्रश्नकर्ता विधायक से कहा कि आप पूरी कागजात को दे दींजिए। मंत्री जी पूरी बात आपको बता देंगे।

एससी-एसटी कल्याण मंत्री ने अंबेदकर आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण

AGENCY CHAMPARAN : जिले के सुगौली प्रखंड के सुगांव स्थित राजकीय अंबेदकर आवासीय विद्यालय का सोमवार को बिहार सरकार के एससी एसटी कल्याण मंत्री जनक चमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई छात्रावास व भोजन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मंत्री ने स्वयं रसोई रूम में जाकर बन रहे भोजन को देखा और भोजन में दिए जाने वाले व्यंजन के बारे में जानकारी ली। छात्रावास का निरीक्षण करते हुए कमरे की साफ-सफाई व रख-रखाव का जायजा लिया। बच्चों को सरकार से मिलने वाली सामग्री व पाठ्य पुस्तक के



अंबेदकर आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करते मंत्री

● फोटोन न्यूज

बारे में जानकारी ली। साथ ही मौके पर मौजूद जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने चाहिए। स्कूल में बेहतर पढ़ाई के साथ ही यहां आवासित बच्चों को मेनू के अनुसार बेहतर भोजन मिले। स्कूल में साफ सफाई ठीक से हो। विद्यालय में किसी तरह की

प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में पांच साल की सश्रम कारावास के साथ तीन लाख रुपये जुर्माना

AGENCY ARARIYA : अररिया एक्सक्लूसिव एक्साइन कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह ने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप रखने के मामले में दोषी को पांच साल की सश्रम कारावास के साथ तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया है। न्यायालय ने विशेष उत्पाद वाद संख्या 161/2022 में सजा सुनाई। मामला अररिया थाना दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। अररिया थाना में पदस्थापित एसएसआई संजीव कुमार ने केस दर्ज कराई थी। 14 दिसम्बर 2021 को गुप्त सूचना पर गैरियारी ओवरब्रिज के निकट सिसौना वार्ड



संख्या पांच अहसान उर्फ तन्नु पिता स्व. अब्दुल जब्बार अपने घर के मचान बनाकर, नीचे कोडीनयुक्त कफ सीरप भारी मात्रा में रखने की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था। पकड़ा गया युवक हासिम पिता स्व.अब्दुल जब्बार था। घर की तलाशी के क्रम में घर से 1170

बोतल प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया था,जिसके बाद पुलिस ने हासिम को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। अहसान उर्फ तन्नु के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। न्यायालय में मो. हासिम के विरुद्ध

आरोप सिद्ध नहीं हुआ और न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन जब अहसान उर्फ तन्नु के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र समर्पित हुआ और न्यायालय में जब यह बात साबित हुई कि प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सीरप के असली मालिक अहसान उर्फ तन्नु हैं तो न्यायालय ने सजा मुक्करर किया और दोषी ठहराया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु कांत मिश्रा ने कम से कम सजा सुनाई जाने की दलीलें दीं, जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मिश्रा और उत्पाद विभाग के अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की मांग की। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।

डीएम ने हाईवे के सभी अवैध कट को चिह्नित कर बंद करने का दिया निर्देश

AGENCY ARARIYA : अररिया जिला पदाधिकारी -नह- अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति अनिल कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिये। बैठक में मुख्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द/निलंबन, हेलमेट चेकिंग, हिट रन से संबंधित सड़क दुर्घटना में मुआवजा की स्थिति, नन हिट रन से संबंधित सड़क दुर्घटना में मुआवजा की स्थिति, तेज गति से वाहन चलाना, बस

स्टॉप का निर्माण, अररिया में ब्लैक-स्पॉट की सूची की गहन समीक्षा की गई।जिलाधिकारी द्वारा जिले में सभी थाना, यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग को हेलमेट चेकिंग हेतु नियमित रूप से विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि जिले के अंदर सभी अवैध कट को चिन्हित किया गया है। इस क्रम में संबंधित विभाग को इन सभी अवैध कटों को बंद करने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश किया गया, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी हो सके। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां अंडर पास के निर्माण हेतु संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया।

आस्था श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव पर निकली निशान शोभायात्रा

श्याम भक्तों ने मंदिर परिसर में खेली फूलों की होली

AGENCY ARARIYA : फारबिसगंज में सोमवार को श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से एकादशी के मौके पर श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव पर निशान शोभायात्रा निकाली गई। स्थानीय सुल्तान पोखर स्थित श्री वीर हनुमान ठाकुरबाड़ी परिसर ने निकली निशान शोभायात्रा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक, सदर रोड, स्टेशन चौक होते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी स्थित श्री श्याम मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। निशान शोभायात्रा में जहां एक तरफ बाबा श्याम का जयकारा लगता रहा, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के द्वारा कलियुग का राजा खाटू नरेश जैसे भजनों की

» एक तरफ बाबा श्याम का जयकारा लगता रहा, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने कलियुग के राजा खाटू नरेश जैसे भजनों की शानदार प्रस्तुति दी

» मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने की बाबा श्याम के चरणों में भजनों की वर्षा



भी शानदार प्रस्तुति दी गई। शोभायात्रा में शामिल महिलाओं के द्वारा खाटू नरेश के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया।

महिलाओं में पूरे रास्ते भर में बाबा श्याम के भजनों में नाचते गाते आगे बढ़ते रहे। निशान शोभायात्रा के उपरांत मंदिर

परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं के द्वारा बाबा श्याम के चरणों में भजनों की वर्षा की गई। साथ ही साथ पुष्प एवं इत्र की

वर्षा बाबा श्याम पर करते हुए भक्तों पर भी किया गया। वहीं शोभायात्रा के दौरान भक्तों द्वारा रास्ते भर में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। मंदिर परिसर में महिलाओं ने श्याम प्रभु के संग फूलों से होली खेलकर जमकर नृत्य किया। इस मौके पर अनिल पांडेय, देवाशीष पांडेय के नेतृत्व में पूजा-अर्चना की गई, जबकि मंदिर परिसर की ओर से संयोजक पवन शर्मा और पवन अग्रवाल आदि के द्वारा शोभायात्रा में शामिल भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह निशान शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेय जल एवं शर्बत, चॉकलेट व फलों की व्यवस्था की गई थी।

AGENCY ARARIYA : डीएम अनिल कुमार तथा एसपी अंजनी कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय अररिया स्थित परमान सभागार में सोमवार को विधि व्यवस्था एवं होली को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई,जिसमें जिले में 225 स्थलों पर स्टैटिक दंडाधिकारी और स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई।इसके अलावा अररिया में 16 एवं फारबिसगंज में 16 गश्ती दल, दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। विधि व्यवस्था संधारण की समीक्षात्मक बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, थाना जनता दरबार, लोक भू-अतिक्रमण, थाना भवन



के लिए भूमि की उपलब्धता, अनाधिकृत धार्मिक संरचना, उत्पाद विभाग एवं विधि प्रशाखा, निलाम-पत्र, खनन, शस्त्र नवीकरण, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन, न्यायालय वाद,कल्याण, लोक शिकायत निवारण, सीसीटीवी अधिछापन के कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी द्वारा होली पर्व के अवसर पर शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों, शरारती तत्वों, उपद्रवियों, अबीर गुलाल फेक जाने, जबरन चंदा वसूली, विवादास्पद कादृत्,अश्लील गाना बजाना आदि विवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

शैक्षणिक छवि की चिंता का समय

ओडिशा स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट आफ इंस्टिट्यूल टेक्नोलाजी (केआईआईटी) में नेपाली छात्रा की असामयिक मृत्यु न केवल दुखद और संवेदनशील मामला है, बल्कि यह भारत की शैक्षणिक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। केन्द्र सरकार ने इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है और पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया है। इसके बाद करीब 1000 नेपाली छात्र केआईआईटी वापस लौटे हैं, लेकिन यह मामला केवल न्यायिक जांच तक सीमित नहीं रह सकता। इसके दो पहलू हैं, जिन पर भारत के नीति-निमाताओं को विचार करने की आवश्यकता है। पहला, नेपाल बीते वर्षों में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदल चुका है। भारत को इन बदलावों का संवेदनशीलता से आकलन करना होगा। दूसरा, यदि भारत को दक्षिण एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना है तो अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेषकर अपने पड़ोसी और मित्र देशों के विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित, संवेदनशील और समावेशी शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना होगा। इस तरह की घटनाएं इन देशों के साथ हमारे रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं। चीन जैसे देश जो लंबे समय से नेपाली युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अवसरों का उपयोग भारत की छवि को कमजोर करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारत अपने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और समावेशिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। साथ ही नस्ली, लैंगिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को संस्थागत ढांचे का अभिन्न अंग बनाए, ताकि सभी छात्र भयमुक्त माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेपाल भारत का एक खास पड़ोसी देश है। वह चाहे एक साझा संस्कृति की बात हो या सामाजिक और धार्मिक समानता, भाषा की या फिर लोगों के बीच आपसी संबंध की। भारत और नेपाल के बीच सामरिक ही नहीं, बल्कि एक मजबूत साझा सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक, सैन्य, शिक्षा, खुली सीमा और लोगों के बीच पारस्परिक संबंध हैं। शायद यही कारण रहा है कि संबंधों में यदा-कदा मन मुटाव के बावजूद बातचीत का माहौल हमेशा से बना रहा है। पिछले दो दशकों में नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। इसके चलते नेपाल एक संवेदनशील देश बन चुका है। इसका असर भारत-नेपाल संबंधों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम इस प्रयास में हैं कि चीन जैसी ताकत नेपाल के रास्ते भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान न कर सके। एक समय था जब नेपाली छात्रों और कामगारों के लिए भारत ही प्रमुख गंतव्य हुआ करता था। खुली सीमा के कारण भारत अनुज-जाना न केवल आसान, बल्कि किफायती भी था। भारत सरकार की छात्रवृत्तियां नेपाली विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर खोलती थीं, लेकिन बीते दो-तीन दशकों में यह स्थिति काफी बदल गई है। विशेष रूप से 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन ने नेपाल के राजनीतिक सोच और विदेश नीति को नया स्वरूप दिया है। इसके साथ नेपाल में विदेश में रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करने वाली एजेंसियों का उदय हुआ है। एक समय जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पूर्वांचल विश्वविद्यालय नेपाली छात्रों के गढ़ माने जाते थे, जिसने भारत के प्रति नेपाल में एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद की, लेकिन अब वह बदल चुका है। यह बदलाव केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी दिखता है। आज अधिकतर नेपाली शिक्षित देशों को लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे में भारत के प्रति जनता की राय में बदलाव आया है। इसका बड़ा फायदा चीन उठा रहा है, जो नेपाली छात्रों को लुभाने में लगा है। इसके परिणामस्वरूप भारत और नेपाल के बीच कोई भी राजनीतिक विवाद अब तुरंत इंटरनेट मीडिया पर छा जाता है। भारत के शैक्षणिक संस्थान न केवल दक्षिण एशिया और अफ्रीका, बल्कि विश्व भर के छात्रों के लिए आकर्षक केंद्र हैं। ये छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर अपने देशों के उच्च पदों पर पहुंचते हैं और दीर्घकालिक रूप से भारत के साथ मजबूत राजनयिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के वाहक बनते हैं। भारत की साफ्ट पावर को भी सुदृढ़ करते हैं, लेकिन ऐसी त्रासद घटनाएं भारत की वैश्विक शैक्षणिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं और इसके भू-राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं। नेपाली छात्रा की दुखद मृत्यु एक चेतावनी है कि भारत अपने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा, प्रशासनिक संवेदनशीलता और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता दे। एक समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण न केवल भारतीय छात्रों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी आवश्यक है, जो भारत को अपनी शिक्षा और भविष्य के निर्माण के लिए चुनते हैं। इस दिशा में दो महत्वपूर्ण सुधार अनिवार्य हैं-पहला, एक उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र, जो छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुने और उनका समाधान करे। दूसरा, चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट का समय रहते सामना किया जा सके। केवल इसी तरह हम भारत को एक वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में मजबूत कर सकते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं।



अरुण कुमार दीक्षित

भारत की राष्ट्रभाषा अपनी ही होनी चाहिए। जैसा कि पूरी दुनिया के अधिकतर देशों में स्वयं की भाषाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी का इस प्रकार विकास किया जाए कि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसके सरल और सुबोध स्वरभाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में भारत की किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की स्वीकृति नहीं है। हालांकि हिंदी एवं अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना जाता है। संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। संविधान में 22 भाषाओं में किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुनाव कर सकेगी। यह भाषाएं हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु , बोडो, डोगरी, बंगाली, उर्दू और गुजराती हैं। केन्द्र सरकार ने कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना है। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय भाषाएं लागू की गई हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में दक्षिण भारत के गोपाल स्वामी आयरंगर ने रखा था।

हिंदी को लेकर एक बार फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहस जारी है। सबसे अपने-अपने दावे हैं। राजनीतिक घाटे-मुनाफे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया कि सरकारी दम्तरों से हिंदी हटाएं, तमिल लागू करें। हिंदी सभी भाषाओं को समाप्त कर देगी। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत की राष्ट्रभाषा अपनी ही होनी चाहिए। जैसा कि पूरी दुनिया के अधिकतर देशों में स्वयं की भाषाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी का इस प्रकार विकास किया जाए कि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसके सरल और सुबोध स्वरभाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में भारत की किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की स्वीकृति नहीं है। हालांकि हिंदी एवं अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना जाता है। संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। विकल्प है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें स्वयं चाहें तो 22 भाषाओं में किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुनाव कर सकेगी। यह भाषाएं हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु , बोडो, डोगरी, बंगाली, उर्दू और गुजराती हैं। केन्द्र सरकार ने कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना है। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय भाषाएं लागू की गई हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में दक्षिण भारत के गोपाल स्वामी आयरंगर ने रखा था।



जाए। मैं समझता हूं कि इस पृष्ठभूमि में जिस बात का उपबंध संविधान में है, वह सामान्यतः स्वीकार्य है कि हिंदी सीखनी चाहिए। देश में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, परंतु इसे वह महत्वपूर्ण स्थान तभी मिल सकता है, यदि हम इस उद्देश्य को सद्भावना से प्राप्त करें। संविधान सभा में कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि भाषा संस्कृति का आधार होती है और संस्कृति राष्ट्रों के इतिहास और जीवन हैं। उनका उत्थान विकास का आधार होता है। संविधान लागू हुआ तब यह व्यवस्था दी गई कि 1965 तक यानी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक सीमा पूरी होती, उससे पहले 1957 में ही अंग्रेजी हटाओ मुहिम को सक्रिय आंदोलन में डॉ. लोहिया ने बल दिया। लोहिया का मानना था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संघ की भाषा हिंदी होगी। यह भी कहा था कि अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का मतलब हिंदी लाओ नहीं है, बल्कि मातृभाषा, लोक भाषा के बिना लोक राज असंभव है। अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग को बंद करने की मांग की लोहिया हिंदी के बड़े पैरोकार थे। लोहिया हिंदी के विकास में ही लोकतंत्र का विकास देखते थे। उनका मानना था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में मातृभाषा का प्रयोग न के बराबर आम जनता की प्रजातंत्र में शत-प्रतिशत भागीदारी के रास्ते का रोड़ा है। वे संसद में कम समय ही रहे। लोहिया संसद में अंग्रेजी में कभी नहीं बोले। वे

कहते वोट लोक भाषा में मांगते हैं, चुनाव बाद अंग्रेजी बोलना लोकद्वेष है। डॉ. लोहिया का भाषा चिंतन विशेष प्रकार का था। गांधीजी के बाद डॉ. लोहिया स्वतंत्र भारत के अकेले नेता रहे जो भाषा के विषय पर राष्ट्रीय संदर्भ में विचार करते थे। वे अंग्रेजी को सामंती भाषा बताते हुए खतरों से आगाह करते रहे। कहा कि यह श्रमिकों, किसानों और शारीरिक श्रम करने वालों की भाषा नहीं है। अखिल भारतीय अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन के प्रथम सम्मेलन का अधिवेशन नासिक महाराष्ट्र में 28, 29 कि अक्टूबर 1959 को हुआ। अधिवेशन में कई प्रांतो के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हिंदी भाषा के अखिल भारतीय महत्व का पहला कारण यह है कि वह भारत की सबसे बड़ी भाषा है। लोहिया ने बल दिया। दूसरा कारण यह है कि उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र तक की भाषाओं और हिंदी के शब्द भंडार में इतनी ज्यादा समानता है कि लोग उसे आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा कारण है राजस्थान के व्यापारी और पूंजीपति भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं और साधारणतः हर जगह हिंदी शिक्षा के प्रचार प्रसार आदि में सहायता करते हैं। चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदी भाषा इलाके के मजदूर मुंबई कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े नगरों में भारी संख्या में मिलते हैं। डॉ. सुनीत कुमार चाटुर्ज्या ने 1948 के अंतरराष्ट्रीय भाषाविद् सम्मेलन (पेरिस) में यह प्रस्ताव रखा था कि संसार में किसी भाषा के समझाने बोलने वालों के विचारों से हिंदी का नंबर तीसरा है। इसलिए

अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, रूसी और चीनी के साथ हिंदी को भी राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा मंजूर करना चाहिए। यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। भारत जैसे देश की एक भाषा राष्ट्र संघ में अश्वय होनी चाहिए। रवींद्रनाथ ठाकुर जैसे मनीषियों ने भगीरथ प्रयत्न किया। गांधीजी ने इस बात का जोरदार आंदोलन किया कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। उन्होंने जापानी की मिसाल देकर बताया कि वहां के लोगों ने यूरोप की विद्या ग्रहण की है, अपनी भाषा के माध्यम से। उनका शिक्षण जापान में होता है, न कि अंग्रेजी में। राष्ट्रीय आंदोलन की यह मांग रही है कि शिक्षा संस्थानों से लेकर न्यायालयों तक में जो सारा काम अंग्रेजी के माध्यम से होता है, वह बंद होना चाहिए। अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं के जो हक छीने हैं, वह उन्हें वापस मिलने चाहिए। तब हम कैसे मानें कि अंग्रेजी यहां लादी न गई थी। और उसे गौरव स्थान देने के लिए यही के देशभक्तों ने प्रयास किया था। अंग्रेजी से कुछ सीखना एक बात है। अंग्रेजी को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का माध्यम बना लेना दूसरी बात है। भारत के नवीन सांस्कृतिक जागरण में अंग्रेजी के महत्व को बढ़ा-चढ़ा कर आंका जाता है। अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त विचारधारा इस जागरण की प्रमुख धारा नहीं रही। प्रमुख धारा के तत्व भारतीय ही रहे हैं। डॉ. रामविलास शर्मा (पृष्ठ 380,393 भाषा और समाज) हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत ने कहा था कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह हमारी भावनाओं, विचारों की सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। निराला ने हिंदी को सशक्त और समृद्ध बताया है। उनका कहना है हिंदी केवल भाषा नहीं है, यह एक क्रांति है। जनता की भाषा है। जनता जब जागेगी तो हिंदी के माध्यम से ही अपनी शक्ति प्रकट करेगी। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा, मातृ भाषा है। हिंदी हमारी संस्कृति है। हिंदी के अधिकतम प्रयोग और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए लगातार वैचारिक अभियान चलाया जाना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर स्टालिन सरकार का अड़ियल रुख

शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार और केन्द्र सरकार की खासी रस्साकशी चल रही है। आठ महीने पहले तमिलनाडु सरकार ने अपनी खुद की शिक्षा नीति (एसईपी) बनाने के लिए जस्टिस मुरुगेसन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह नई शिक्षा नीति कब लागू होगी। राज्य सरकार के अड़ियल व्यवहार तथा राजनीतिकरण से तमिलनाडु राज्य के विद्यार्थियों का भविष्य अंधर में लटक हुआ है। दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू की है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। तमिलनाडु सरकार को इस नीति के कुछ हिस्सों से विशेष आपत्ति है। केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में वह अपनी अलग शिक्षा नीति बनाना चाहती है। इसी कारण से एसईपी में देरी हो रही है। केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एनईपी लागू करने के लिए बार-बार कह रही है। केंद्र के निदेशों के अनुसार जो संस्थान इसे लागू नहीं कर रहे हैं, उनकी फंडिंग रोकी जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार



ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु की 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडिंग रोक दी है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान एनईपी को लागू करेंगे, उन्हें बेहतर ग्रेडिंग दी जाएगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एनईपी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए छात्रों को एनईपी एम्बेसडर बनाने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि एनईपी के कुछ पहलू छात्रों के हित में नहीं हैं। सरकार को खासतौर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट (एमईएमई) प्रणाली से आपत्ति है। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि एबीसी में पारदर्शिता की कमी है और एमईएमई से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर

बुरा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार के निदेशों के अनुसार, मद्रास विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय जैसे कई राज्य विश्वविद्यालय एनईपी के कुछ हिस्सों को लागू कर रहे हैं। मद्रास विश्वविद्यालय ने एबीसी प्रणाली लागू कर दी है और छात्रों के लिए एक गाइड भी जारी किया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि अगर वे एबीसी लागू नहीं करते हैं तो उन्हें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अन्ना विश्वविद्यालय ने भी एमईएमई प्रणाली लागू कर दी है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इसे छात्रों को शिक्षा में विशेष सुविधा मिलेगी। पूर्व अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति ई. बालागुरुसामी का कहना है कि एनईपी के उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन इसे जल्दबाजी में लागू करना सही नहीं है। उनका मानना है कि ऑनलाइन प्रवेश और दोहरी डिग्री जैसे कदम शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राज्य साझा स्कूल प्रणाली - तमिलनाडु (कामन स्कूल सिस्टम-तमिलनाडु) के अध्यक्ष पी. रत्नसबपति का कहना है कि यूजीसी सिर्फ एक मार्गदर्शक संस्था है और उसके पास दंड देने का अधिकार नहीं है। उनका मानना है कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी

सूची से हटाने की धमकी देना यूजीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। केंद्र सरकार एनईपी को लागू करने में तेजी लाई है। हाल ही में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए नो डिटेनशन पॉलिसी को हटा दिया गया है। अब अगर छात्र परीक्षा में फेल होते हैं तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। इसी प्रकार एनईपी के तहत 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जा रही है, जो पुरानी 10+2 प्रणाली को बदल रही है। क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार एनईपी को और अधिक व्यापक रूप से लागू करने पर ध्यान दे रही है। तमिलनाडु सरकार को अपनी शिक्षा नीति पर जल्द ही फैसला लेना होगा। यह देखना होगा कि तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार के दबाव में अपनी नीति लागू करती है या नहीं। वैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस उपलब्ध का सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस नीति के अनुसार पढ़ाई करनी है। तमिलनाडु सरकार के हठ से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी अनिश्चितता का माहौल है।

Social Media Corner

सब के हक में...

पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक महीने से अधिक हो गया है। मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगें की थीं, वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है।

(राहुल गांधी का 'एक्स' पर पोस्ट)

गढ़वा जिले के रंका थाना अंतर्गत गोदरमाना में पटाखा दुकान में आग लगने से 5 लोगों के मृत्यु की दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दें। जिला प्रशासन पीड़ित परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराए एवं पटाखा दुकानों को खुले स्थानों पर सभी मानकों के अनुरूप संचालित करने का दिशानिर्देश जारी करे।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

सावित्रीबाई फुले : महिला शिक्षा की अग्रदूत

सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार को अपने जीवन का मिशन बना लिया। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने, कुआड़ूत मिटाने और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए समाज की रूढ़िवादी सोच से जमकर संघर्ष किया। उस दौर में महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था। हालांकि इसात्मिक आक्रमणों से पहले भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी लेकिन बाद में उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। सावित्रीबाई ने इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं के जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलाने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। समाज के दकियानूसी लोगों ने उन पर कीचड़ फेंका, उनका अपमान किया लेकिन वे अड़िग रहीं। उनके विवाह के समय वे मात्र 9 वर्ष की थीं, जबकि उनके पति ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे। यह विवाह 1840 में संपन्न हुआ। पेशवाओं द्वारा पुणे में दिए गए एक उपहार स्वरूप बगीचे के कारण उनके परिवार को 'फुले' उपनाम मिला। सावित्रीबाई अपने मायंक से एक पुस्तक लेकर आई थीं। इस पुस्तक ने न केवल उनके पति को प्रेरित किया, बल्कि दोनों को शिक्षा की ओर उन्मुख किया।

स्वयं शिक्षित होने के बाद उन्होंने समाज में शिक्षा का प्रसार करने का बीड़ा उठाया। 1 मई 1847 को, उन्होंने पुणे के सगुनाऊ क्षेत्र में पहला स्कूल खोला, हालांकि यह अधिक समय तक नहीं चल सका। इसके बाद, 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिडे वाड़ा में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत में किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा स्थापित पहला बालिका विद्यालय था। शुरूआती दौर में इस स्कूल में मात्र छह छात्राएं थीं, लेकिन वर्ष के अंत तक यह संख्या 40-45 हो गई। बाद में 18 सितंबर 1851 को पुणे में और 15 मार्च 1852 को बताल पैठ में और विद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। इससे पहले 1829 में अमेरिकी मिशनरी सिथिया फरर ने मुंबई में लड़कियों के लिए एक स्कूल की शुरूआत की थी। पारसी समुदाय ने भी 1847 में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला था। सावित्रीबाई ने सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए निरड होकर संघर्ष किया। उन्होंने विधवाओं के शोषण को रोकने के लिए पुणे में नाइयों की हड़ताल का आयोजन किया, ताकि विधवाओं का सिर जबरन न मुंडवाया जाए। उन्होंने रात्रि

विद्यालयों की शुरूआत की, ताकि दिन में मजदूरी करने वाले श्रमिक रात में शिक्षा प्राप्त कर सकें। जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी उन्होंने प्रभावी कदम उठाए। जब उन्होंने देखा कि दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता, तो उन्होंने अपने घर का कुआं सभी के लिए खोल दिया। यह उस समय का एक क्रांतिकारी कदम था, जो सामाजिक समरसता की मिसाल बना। सावित्रीबाई ने विधवा महिलाओं के लिए भी अनूठी पहल की। उन्होंने एक गर्भवती विधवा को आत्महत्या करने से रोका, उसकी डिलीवरी अपने घर पर कराई और उसके पुत्र को पाल-पोसकर डॉक्टर बनाया। 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैल गई। सावित्रीबाई और उनके पति ने पीड़ितों की निःस्वार्थ सेवा की। इस दौरान, वे स्वयं भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था यदि किसी देश की प्रगति को मापना हो, तो वहां की महिलाओं की शिक्षा को देखना चाहिए। सावित्रीबाई फुले ने अपने कार्यों से इस कथन को सिद्ध किया। आज, उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि महिलाएं न केवल शिक्षित हो रही हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं। सावित्रीबाई फुले के योगदान को सदा स्मरण किया जाएगा।

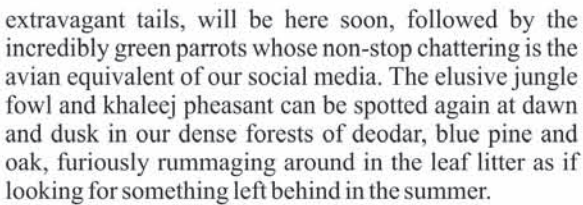
हिमालयी त्रासदी

उत्तराखंड के माणा गांव में हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की टीमों ने फाहेदार और ठोस बर्फ के मलबे में फंसे 23 मजदूरों को बचाया। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां आठ कंटेनरों में 54 मजदूर रह रहे थे, घटी इस आपदा में आठ कामगारों की मौत हो गयी। इतना भर कहना नाकाफी होगा कि बचाव अभियान दुष्कर था। बचाव दलों ने समुद्र तल से 10,500 फुट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच 60 घंटे की तकरीबन लगातार शिफ्ट में काम किया। बर्फ से अवरुद्ध सड़कों को देखते हुए मलबे से निकाले गये लोगों को हेलीकॉप्टरों (पांच हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के, दो वायुसेना के और एक नागरिक हेलीकॉप्टर) से जोशीमठ सेना अस्पताल पहुंचाया गया। निकासी में लगाए गए शारीरिक प्रयास के साथ-साथ, बचाव अभियान ने फाहेदार बर्फ, ठोस बर्फ और चट्टान के नीचे दबे कंटेनरों का पता लगाने के लिए ड्रोन आधारित डिटेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। भारतीय क्षेत्र की आखिरी चौकियों में शामिल और चीन से लगी सीमा के करीब माणा में जिस तरह का हिम-स्खलन हुआ, वह हिमालयी राज्यों में अनोखा नहीं है। यहां के गांववाले ऐतिहासिक रूप से शीत-प्रवासी रहे हैं, जिसका मतलब है कि सर्दियों के महीनों में गांव सूना होता है। नवंबर में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की रस्म के साथ, जाड़े के लिए, नीचे की ओर स्थित गोश्वर और ज्योतिर्मठ जैसे गांवों की ओर प्रवासन होता है। गांव के निवासी अप्रैल या मई में मौसम दोबारा खुलने पर ही लौटते हैं। यह पारंपरिक समझ-बूझ का हिस्सा है और इसका संबंध ऊपरी हिमालयी क्षेत्र के आपदाओं के जोखिम से ग्रस्त रहने के अनुभव से है। इस परिपटी ने भले ही गांव के निवासियों को बचा लिया हो, लेकिन तब भी यह सवाल उठता है कि क्या कामगार जिनमें से कई प्रवासी थे, अपने काम के जोखिम के खतरों से समुचित रूप से अवगत थे।

Changing colours amid the bloom

I am, however, unequivocally abstemious of well-intentioned compliments from readers.

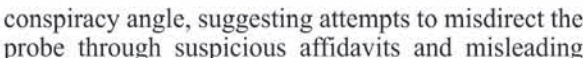
The willows and wild rhododendrons are the first to start leafing and flowering, followed by the rock begonias, hydrangeas, geraniums and nasturtiums: my garden explodes with a new colour every day. The roses, as befits their exalted status, make me wait another month before flashing their blood-red visiting cards. Among the fruit trees, the apricot blossoms stain the landscape a soft pink by the end of March; a few weeks later, the apple and 'nashpati' flowers, too, will add their lilac and white hues to nature's palette. On cue, the butterflies, bees and bumblebees miraculously reappear, though sadly not in the numbers of 15 years ago when I first arrived here. They flit frantically from flower to flower as if renewing friendships of the previous year. There used to be dragonflies earlier but they have now gone. The tiny songbirds, barbets and Himalayan magpies, with their



After seven months of living in a neon-reflecting grey shroud, I can see the sun and the stars again, greeting the morning orb with a prayer and wonder in my heart: is this the same sun that one dreads in Delhi? The night sky is like a star-sequined bosom pressing down on my upturned face — silent, comforting and all-embracing. The only occasional sound is that of a jackal complaining plaintively of his lot in life or the learned hoot of a barn owl. It's Eden without the serpent. The whole village comes to life again: kids in smart new uniforms hop their way to school, labourers from Nepal and Bihar return to jobs in construction and orchards, even the PWD

Hathras stampede


The Hathras stampede of July 2, 2024, which claimed 121 lives, stands as yet another grim reminder of administrative negligence, lack of planning and the perils of unregulated mass gatherings. The judicial inquiry report, tabled in the Uttar Pradesh Assembly on Wednesday, exposes glaring lapses in crowd management, haphazard permissions and a troubling abdication of responsibility by the authorities. The most damning revelation is the mechanical approval of the event. The permission process, completed in a day without any site inspection, reeks of bureaucratic complacency. The organisers estimated 80,000 attendees, yet over 2.5 lakh devotees swarmed the venue. Despite this, no proactive crowd control measures were in place. Water tankers stationed near a muddy highway created a treacherous ground and sevadars — rather than trained personnel — were tasked with managing the crowd. The report also hints at a



and foul the little streams. Fruit trees are felled and whole orchards razed to make way for these pestilential structures. Grazing fields have been built over, to the point where villagers have stopped rearing cattle because there is no grazing available. So, now, milk, butter, ghee and even manure are brought in from outside in plastic bags.

The policymakers have devastated the towns in their quest for quick bucks from a tourism model that is unsustainable; they should not repeat this mistake in rural areas like Purani Koti. Promote only homestays and B+B's: these do not involve diversion of precious farm land or orchards, do not strain infrastructure yet provide profitable livelihood options for the villagers.

This is, of course, wishful thinking; it will not happen in my lifetime. I don't think my little Eden will retain its natural splendour much longer. I only hope that I've shuffled off this mortal coil when the serpents take over.

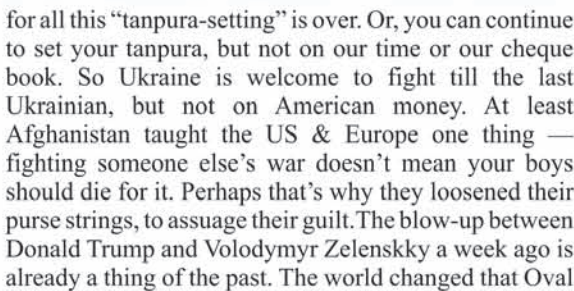


narratives. Yet, in its reluctance to directly indict Bhole Baba, the panel leaves room for ambiguity. The absence of his name from the FIR and charge-sheet raises uncomfortable questions — does faith shield individuals from accountability? The recommendations, including mandatory videography, stricter permission protocols and the use of drones for crowd-monitoring, are welcome. But the real challenge lies in ensuring their implementation. In a country where religious gatherings at times morph into stampedes (Maha Kumbh being the latest), will this tragedy serve as a wake-up call or merely be buried under bureaucratic inertia? The Hathras disaster wasn't an accident; it was an avoidable catastrophe. Holding mid-level officials accountable while letting powerful organisers off the hook cannot be the takeaway. The state must move beyond damage control and enforce real, systemic reforms.

Trump-Putin-Modi summit is doable

THE GREAT GAME: Can the PM, whose foreign policy dexterity must be applauded, take a leaf out of Virat's book?

What is amusing is that the Europeans and Britain are this shocked. The British and the French, both Security Council permanent veto powers — as well as all those other nations on the Continent trying desperately to assert themselves on the world stage — have kowtowed to the Americans at least since the end of the Second World War, riding piggyback on the strength of the American dollar. Europe's worst-kept secret is the barely hidden contempt the Europeans have for the ugly American — except they want their money. The most overpriced baguettes the other side of Suez are manufactured by Parisians in the summer — when Paris empties itself in anticipation of the hordes of American tourists descending upon the French capital, all looking for one or another version of A Moveable Feast a la Hemingway. The thing about Trum & Co — JD Vance, Elon Musk and the lot — is that they have no time for what well-known journalist Shekhar Gupta calls “tanpura-setting.” Meaning, all the frills and the fuss that Europe loves so much, couched in words like “egalite” and “liberte” and even “fraternite” — although you should, dear Reader, check out France's not-long-ago record in North Africa, especially Algeria, where even the White French were dismissively known as “pied noir” or “black feet,” because they weren't white enough for Mainland French — is all so soul-stirring and uplifting because at the end of the day they know that the bill will be picked up by the Americans across the pond. Well, Trump & Vance just announced that the time



Office morning and the world saw the raw exercise of power. If Europe — and the Ukrainians — fulminated about the lack of grace and courtesy in the exercise of that power, perhaps they're right. But they also know that it's not easy to make omelettes if you can't break a few eggs. What is amusing is that the Europeans and Britain are this shocked. The British and the French, both Security Council permanent veto powers — as well as all those other nations on the Continent trying desperately to assert themselves on the world stage — have kowtowed

to the Americans at least since the end of the Second World War, riding piggyback on the strength of the American dollar.

Europe's worst-kept secret is the barely hidden contempt the Europeans have for the ugly American — except they want their money. The most overpriced baguettes the other side of Suez are manufactured by Parisians in the summer — when Paris empties itself in anticipation of the hordes of American tourists descending upon the French capital, all looking for one or another version of A Moveable Feast à la Hemingway.

The thing about Trump & Co. — JD Vance, Elon Musk and the lot — is that they have no time for what well-known journalist Shekhar Gupta calls “tanpura-setting.” Meaning, all the frills and the fuss that Europe loves so much, couched in words like “egalite” and “liberte” and even “fraternite” — although you should, dear Reader, check out France’s not-long-ago record in North Africa, especially Algeria, where even the White French were dismissively known as “pied noir” or “black feet,” because they weren’t white enough for Mainland French — is all so soul-stirring and uplifting because at the end of the day they know that the bill will be picked up by the Americans across the pond. Well, Trump & Vance just announced that the time for all this “tanpura-setting” is over. Or, you can continue to set your tanpura, but not on our time or our cheque book. So Ukraine is welcome to fight till the last Ukrainian, but not on American money. At least Afghanistan taught the US & Europe one thing — fighting someone else’s war doesn’t mean your boys should die for it. Perhaps that’s why they loosened their purse strings, to assuage their guilt. Virat Kohli, about whom the PM admirably tweets and often, showed the way some days ago when he bent over to tie the shoelaces of the Pakistani batsman he was playing against — a calm confidence about himself, his game and his place in the world.

Stock market bounces back, but will the relief rally last

New Delhi. The domestic stock market continued its positive run for the third straight session after a prolonged period of correction. The S&P BSE Sensex gained nearly 400 points in early trade, while the NSE Nifty50 also rose sharply. At around 11:42 am, the Sensex was up 297.11 points higher to 74,629.69 and the Nifty was trading 79.40 points higher at 22,631.90. All the other broader market indices were mixed. Overall, the situation on Dalal Street looks much better than how it appeared at the beginning of last week. Does this mean investors can take it easy now? Unfortunately, experts are not too optimistic about the ongoing recovery rally. The Nifty's strong run last week was backed by slowing FII selling, but analysts say the rally may not have much steam left.

Dr. V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services, pointed out that "market momentum witnessed last week is unlikely to continue beyond a point since the element of uncertainty is high." One major concern is the possibility of reciprocal tariffs on India starting in April. There's no clear picture yet on which sectors will take the hit, keeping traders on edge.

Vijayakumar advised investors to focus on domestic consumption stocks, saying, "Export-oriented segments like IT and pharma will be volatile responding to news flows surrounding US actions."

Prashanth Tapse, Senior VP (Research) at Mehta Equities, also flagged caution, noting that despite some positive signals from the US Fed, concerns around Trump's tariff policies are keeping investors nervous. FIIs have already pulled out a massive Rs 4.13 lakh crore this fiscal year. On the technical side, Anand James, Chief Market Strategist at Geojit, sees some danger signs. "The shooting star candlestick formation on Friday points to indecision or a potential down move," he said.

Explained: Why IndusInd Bank shares fell over 5% in early trade

New Delhi IndusInd Bank shares took a hit on Monday, dropping over 5% in early trade on the Bombay Stock Exchange (BSE). The stock fell 5.4% to a day's low of Rs 886.4 on the Bombay Stock Exchange (BSE) in early trade. At around 10:20 am, shares of the company were trading 3.13% lower at Rs 907.45.

The sell-off came after the Reserve Bank of India (RBI) decided to give CEO Sumant Kathpalia just a one-year extension instead of the three-year term the board had wanted. It may be noted that this isn't the first time RBI has cut short his tenure last time too, the regulator didn't approve a full term. Investors weren't happy, and the stock has been on a rough ride. In the past year, it's down nearly 42%. In the last six months, it is down over 36%, and 8% in the past five trading sessions.

Brokerages see trouble ahead. Emkay Global slashed its target price from Rs 1,400 to Rs 1,125, though it still kept a 'buy' rating. It warned that the RBI's move could lead to instability at the top and shake up the bank's strategy. Even after the cut, the new target still means a possible 27% upside.

Nuavama, on the other hand, was much more pessimistic. It pointed to weak microfinance conditions, poor earnings visibility, and the risk of an outsider taking over as CEO. It expects the stock to stay under pressure. Kathpalia has been at the helm for five years, steering the bank's stock from Rs 398 to Rs 936 before this latest drop. But concerns over bad loans in the microfinance segment and leadership uncertainty have rattled investors. The RBI usually gives bank CEOs a three-year term, so its decision raises eyebrows. Many see it as a sign the regulator isn't fully convinced about the bank's leadership.

Tame volatility for creating wealth

New Delhi. Investing in a volatile market can feel like navigating a storm, but with the right strategies, you can manage risks and even find opportunities. There's a Tamil saying 'you can't wait for the tides to stop if you want a dip in the ocean' Here's a practical breakdown based on timeless principles and current market dynamics!

1. Understand and accept volatility
Volatility means rapid price swings—up and down. It's driven by uncertainty, economic shifts, geopolitical events, or market sentiment. Right now, markets might be reacting to inflation concerns, interest rate changes, or tech sector disruptions, geo-politics, etc. Knowing why the market's jittery helps you stay calm and strategic. However, trying to specifically find out which factor impacts how much is a total waste of time.
2. Diversify your portfolio
Don't put all your eggs in one basket. Spread investments across:
 - Stocks: Mix stable large cap, mid-cap, small-cap mutual funds.
 - Debt mutual funds – less risky than bonds.
 - Commodities: Gold, silver – again mutual funds not the commodity directly.
- Cash: Keep some liquidity to scoop up bargains when prices drop.
- REITS – a small way of participating in the expensive retail market. A volatile market punishes over-concentration, so diversification is your shield.
3. Focus on quality Invest in companies with:
 - Strong balance sheets (low debt, high cash reserves).
 - Consistent earnings, even in downturns.
 - Competitive advantages e.g., brand loyalty, patents).
4. Rupee-cost averaging Instead of timing the market, invest a fixed amount regularly. When prices dip, you buy more units; when they rise, you buy fewer. Over time, this smooths out the rollercoaster and reduces emotional stress.
5. Look for opportunities Volatility creates mispricing. Oversold stocks or sectors (e.g., energy during a dip or biotech after a panic sell-off) can be bargains if you've done your homework. Research fundamentals—don't just chase hype.
7. Stay long-term Short-term volatility is noise. If your horizon is 5+ years, temporary drops matter less. Historically, markets recover and grow—think Sensex's resilience since 1979.
8. Manage emotions
Fear and greed spike in volatile times. Stick to a plan. Avoid panic-selling at lows or FOMO-buying at peaks. Data backs this: emotional investors underperform disciplined ones by 2-4% annually.

Why surging household wealth is good news

The latest data published in the National Stock Exchange monthly bulletin reveals that individuals account for 9.8% of the market directly and 18.2% when their mutual fund share is added.

New Delhi. Individual investors are the largest group in the stock market after promoters. The latest data published in the National Stock Exchange monthly bulletin reveals that individuals account for 9.8% of the market directly and 18.2% when their mutual fund share is added. "Individuals thus own more of the Indian markets than FIIs—the first time since 2006," the bulletin states.

That is good news for the depth of the Indian capital markets, which can stay relatively calm even if foreigners continue to exit. The other interesting factor is about the

household wealth. It has increased rapidly and can significantly affect India's future stock market wealth and consumption. It is now estimated at Rs 79.6 lakh crore, growing at an average 10-year rate of 21.3%. It is just under \$1 trillion, which is way higher than \$500bn worth of Indian equities owned by foreign portfolio investors.

Predicting human behaviour is like predicting the rains. Despite a lot of data and information, it is hard to determine future actions. Factors beyond the standard data now affect the weather and us. Stock market trends are hard to predict, too. You need knowledge and an understanding of how you react to situations to manage your money. The NSE publishes a monthly bulletin with information that is easy to understand. Similar bulletins are published by the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India and the Bombay Stock Exchange. To get a sense of financial trends, you must try to read these once a month. You may learn something new. Things you feel are tough to understand; you can ignore them if you do not have anyone to help make sense of them. However, getting into a habit of figuring out future trends

could be a helpful habit while investing. The stock market wealth combined with the gold held by the households makes India's consumers a potent force. Analysts believe the value of gold Indian



households hold is well over \$1 trillion. The households that control that stock market wealth would use it to buy real estate or other assets. They may continue to buy more stocks as new initial public offerings hit the market over the next few years. It is a unique opportunity for businesses to list in India and raise the money needed to fuel growth.

Households can also use that money to spend on luxury, foreign or domestic holidays, weddings, or other key life

goals. That is excellent news for the Indian economy if some portion of the stock market household wealth is used for spending. For India to grow faster, domestic consumers must spend more on lifestyle products. It would be even better if such products were manufactured in India.

What does it mean

If you are a long-term investor in India, there is no reason to panic. While share prices have been hammered over the past few months, it offers an opportunity for Indian investors to enter the market or add more quality companies to their portfolios. The analysis of corporate profits in the NSE bulletin also predicts weaker profit growth for companies in 2025-26. However, many companies expect urban consumption to increase in the second half of 2025-26 and do even better a year later. If share prices continue to fall, the valuation of Indian shares will soon become attractive for all investors.

For those not into direct investing, index or exchange-traded funds offer a good way to gain exposure to equity assets. There is a tendency to cut exposure to systematic investment plans and mutual funds when share prices fall.

EPFO announces new rules for EDLI Scheme: 3 key death benefits updates

New Delhi. The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), in its 237th meeting of the Central Board of Trustees (CBT), announced important changes to the Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) scheme. These updates aim to provide strengthened financial support for the families of employees who pass away while in service.

WHAT IS EDLI?

The EDLI scheme is part of the Employees' Provident Fund (EPF) and acts as a social security benefit. It offers financial assistance to the dependents of an EPF member in the event of the untimely death of the EPF member while still employed. Minimum insurance benefit: As per the announcement, if an employee dies within their first year of service, their family will receive a minimum insurance amount of Rs 50,000.

"A minimum life insurance benefit of Rs. 50,000 will be provided in cases where an EPF member



dies without completing one year of continuous service. This amendment is expected to result in higher benefits for more than 5,000 cases of deaths in service, every year," stated EPFO in its press release. Benefits even after a non-contributory period: Earlier, if an EPF member had a non-contributory period (a time when they were not making EPF contributions) before passing away, their family could be denied the death benefit. However, under the new rule, such cases will now qualify for benefits. "Now, if a member passes away within six months of their last contribution received, the EDLI benefit will be admissible, provided the member's name is not stuck off from rolls," said EPFO. Consideration of service continuity: Previously, even a short employment gap like a weekend or a holiday during a job switch could make families ineligible for death benefits. Families were denied the minimum benefit of Rs 2.5 lakh and the maximum of Rs 7 lakh because the continuous one-year service requirement was not met. "Under the new modifications, a gap of up to two months between two spells of employment will now be considered as continuous service, ensuring eligibility for higher quantum EDLI benefits. This change is expected to benefit more than 1,000 cases of deaths in service, every year," stated EPFO.

Zomato transforms into Eternal Ltd as it expands beyond food delivery

New Delhi. Zomato Ltd has officially received shareholder approval to change its corporate name to Eternal Ltd, marking a significant step in the company's bid to diversify its quick commerce operations. The food-tech giant confirmed the decision in a filing with the stock exchanges. However, the change only applies to the corporate entity and not to the Zomato brand or app. The company reassured users that its food delivery service would continue under the same well-known name. Shareholders approve name change and document modifications In addition to the name change, shareholders also approved amendments to Zomato's Memorandum of Association (MoA) and Articles of Association (AoA). These legal documents will now reflect the new corporate identity. The approval came through a postal ballot, as stated in the company's official communication dated February 6 and February 7. The scrutiniser's report detailing the voting outcome was published on March 9. A strategic shift for the company This rebranding move also aligns with Zomato's long-term vision as it expands beyond food

delivery. Over the years, the company has diversified into various ventures, including Blinkit, Hyperpure, and District, reinforcing its broader tech-



driven ambitions. On February 6, Zomato's board of directors approved the corporate name change, pending regulatory approvals. This marks a new phase of growth as the company strengthens its position across multiple sectors. New corporate website and stock ticker As part of this transition, Zomato will update its corporate website from zomato.com to eternal.com. Additionally, its stock ticker will change from ZOMATO to ETERNAL, aligning with the company's evolving brand identity. CEO Deepinder Goyal explains the move Zomato's CEO, Deepinder

Goyal, provided insights into the name change in a letter to shareholders. He revealed that after acquiring Blinkit, the company internally started using "Eternal" to distinguish between the corporate entity and the Blinkit brand. "The complete criteria for who qualifies for access will be determined at a later stage," Goyal stated, emphasising that this strategic move reflects the company's expanding ambitions. What's next for Zomato (now Eternal Ltd)? The rebranding is expected to strengthen Zomato's market presence and signal its commitment to long-term growth. With a focus on innovation and diversification, the company aims to maintain its leadership in the competitive food-tech and e-commerce ecosystem. While the name on legal documents changes, Zomato's app, service, and brand identity remain unchanged, ensuring a seamless experience for users and partners. Zomato shares were down 1.18 per cent at Rs 214.25 apiece at 11:40 am on Monday, March 10. The stock has declined 22.01 per cent, so far, in calendar year 2025.

AI development risks bias due to underrepresentation of women: Microsoft

New Delhi. The underrepresentation of women in the field of artificial intelligence (AI) poses a significant risk of perpetuating the prevailing societal biases into future technologies, according to a top Microsoft executive. Himani Agrawal, Chief Partner Officer, Microsoft India and South Asia, believes that inclusion is a shared responsibility and if AI continues to be shaped without diverse perspectives, the biases of today risk becoming hardwired into the technology of tomorrow. "This isn't just a number's problem; it's about the future we're building. If AI is shaping the world, then the people shaping AI need to reflect the world's diversity. Otherwise, the biases of today risk becoming hardwired into the technology of

tomorrow. "That's why we need to start early -- sparking curiosity in young girls, strengthening mentorship networks, and ensuring women have the skills and leadership opportunities to drive AI forward," Agrawal said in a conversation with PTL. This holistic approach is crucial to address the "leaky pipeline", where entering the workforce and staying there can feel like an uphill task for many women, she added. This concern is particularly relevant as AI increasingly shapes various aspects of life, from healthcare and finance to education and employment. An AI trained primarily on data reflecting existing societal imbalances could perpetuate those very imbalances, creating a feedback loop of bias.

She shared that women comprise 31.6 per cent of Microsoft's core workforce, and the company is actively working towards better inclusion. The need for greater female participation is especially critical in emerging fields like cybersecurity, where demand is high, but women remain underrepresented. "The real challenge and opportunity lies in ensuring that women don't just enter the workforce but thrive in it. Technology has the power to be an equaliser, offering flexible careers, diverse roles, and limitless possibilities. Yet, the crucial transition from mid-level to leadership remains a hurdle for many women. That's where an inclusive culture makes all the difference," Agrawal said.

Reciprocal tariff to impact pharma, textiles sectors most

New Delhi. With \$87.4 billion, of the \$322-billion merchandise exports in 2024, coming from the US alone, which has threatened to slap 25% duties on our shipments from April 2, is our largest trading partner with 27% of all exports. Of this, domestic companies have shipped goods worth \$87.4 billion to the US, up 4.5% from 2023, while we imported goods worth \$41.8 billion, up 3.4% from them, taking the bilateral trade to close to \$130 billion. But with reciprocal tariffs getting kicked off from next month (no word on services tariffs yet), exports face an uncertain future. Amidst this rising uncertainty, the Export and Import Bank of India (Exim Bank) has held discussions with exporters and also provided their inputs to the commerce ministry on the potential impact of the duty hikes on our exports, which will be significant, Deepali Agrawal, deputy managing director, Exim Bank, tells TNIE's Benn Kochuveedan. Edited excerpts:

The US has announced 25% tariffs on our goods exports. What is Exim Bank's assessment of the impact of the trade war on our exports? A lot of work is being done because the majority of our exports are to

the US. Since the US is our largest trading partner, it will have a significant impact. The exact impact will depend on what the demands are coming in from their side. The problem is that our exports are too concentrated in the US. We have given our inputs to the government on the impact of the reciprocal tariffs that the US will be imposing on our goods from April 2. We've also held discussions with exporters. What are the suggestions you have given to the ministry?

I can't give you the specifics of what we have told the government. But our view is that we must diversify our export basket to other markets like Latin America, Africa, the Middle East, Southeast Asia, where we see a lot of interest for our goods. The point is that shifting or diversifying our focus to other markets should not be merely because of issues with the US. It should be done for the long-term benefits so that issues in one market should not upset our trade in the future. As part of our outreach, we have just opened an office in Sao Paulo, Brazil. We already see a lot of interest being generated from that office. What is your assessment of the likely dumping by



China as it also fights higher US tariffs? The biggest dumping threat will come from Chinese steel mills, which have already been dumping for quite some time. The government has already announced investigations on this.

Which are the sectors that will be hit the hardest? The biggest impact will be on pharma as our companies have the maximum exposure to the US market (around 43% of general medicines sold in the US are made by our companies). Another sector that will have a significant impact will be textiles. Engineering goods will also be impacted. Is the bank seeking

capital infusion from the government this year or next as the ministry is pushing for \$1 trillion merchandise trade? We are well-capitalised now and so not looking for capital infusion from the government. In fact, for the next few years we don't need extra capital to fund our business. Currently, our equity capital is Rs 20,000 crore and the capital adequacy ratio is 26. We have more than enough growth capital with us. Normally we borrow \$3 billion annually, of which 70% are from overseas markets, mostly in dollars, and the rest from domestic sources. But since the pandemic our project export finance, which is around 40% of our assets, has been slowing. Thankfully it has started a marginal revival. This fiscal we've raised only \$1 billion in debt and there is no need for funds now. We have an outstanding dollar debt of \$3 billion now. What is your target for exports this fiscal and the next? Our export forecast for this fiscal is around \$446.5 billion. Of this we have reached already \$397 billion as of January. February data is not out yet. For the next fiscal, assessment will be done next month.

Pressing need to restore dignity of Delhi assembly

NEW DELHI. Democracy blossoms if the legislative wing is firm on its footing; democracy flounders if the legislative wing totters. During the discussion on the Motion of Thanks to the address made by the Lieutenant Governor VK Saxena, Delhi Minister Ashish Sood had an interesting fact to share. He pointed out that during the past five years of the rule of the Aam Aadmi Party in the national capital, Delhi Assembly remained if not non-functional, it was dysfunctional. Sood was referring to a data released by a research agency which mentioned, that in the past five years just 74 sitting of Delhi assembly took place. In these sitting deliberations were made for just 215 hours which is just above 11 minutes per day in the past five years. More interestingly just 180 questions were allowed during these five years, and which only 55 were answered on the floor of the house. These figures indicate that the Arvind Kejriwal government completely demolished the sanctity of the Vidhan Sabha. He kept the assembly floor reserved only for verbal fusillade against his political rivals and the government at the Centre. This he did as the privileges of

the house protected him from inviting any contempt from the people he targeted. The general practise of the functioning of the legislative houses is that the government of the day sends a Cabinet note to the head of the state, President at the Centre, Governor in the states and the Lieutenant Governor in the case of a Union Territory like Delhi, to summon the house to deliberate legislative business. The head of the state on examining the legislative agenda permits the summoning of the house, thereafter the Speaker of the House manages the sittings of the session. At the end of the session, the cabinet again send a note to prorogue the house. Proroguing of the house means end of the session and not the dissolution of the House. For the next session, again a Cabinet note would have to be sent and process followed. This process in a way monitors the agenda which the government of the day seeks to bring before the House. The account of legislative business reflects on the ability of the government to initiate new programmes and policies. Arvind Kejriwal misused this provision to his



advantage. His government would never recommend the prorogation of the house. This allowed him to call 'special sessions' at his whims and fancies and use it to berate his rivals. This he could do as did not need to go to the head of the state to summon the house as it was Speaker's prerogative to resume 'adjourned' house. So the majority of the hours spent in the sitting of the 7th Delhi Assembly (2020-25) was used in shooting acerbic missives at the political rivals as a helpless head of the state watched the misuse of the House. That the House transacted no quality business is evident from the fact that in these five years only 15 bills were passed.

Of these bills passed, five Bills amended laws to increase the salaries and allowances of MLAs, Ministers, the Leader of Opposition, the Chief Whip, the Speaker, and the Deputy Speaker. There was no substantial discussion on these bills or for that matter other bills as the majority of the bills were passed by the House on the very day it was introduced. Even important Budget bill on an average got passed just after two days of discussion. One of the major challenges before the current assembly (the 8th Vidhan Sabha) is to uphold the dignity of the House and reintroduce the culture of debate. The Aam Aadmi Party must realise that their rabble rousing acts, in which they indulged in the first session of the current assembly, would not take them very far. They as opposition must participate in the debate and deliberations of the House. The best way for the opposition to lay a siege of the government is to waylay it on the floor of the House through articulate debates. Given the live streaming of the debates, it would also give them the opportunity to take their views to the people.

ED raids Bhupesh Baghel's son in Chhattisgarh liquor scam

Chaitanya Baghel's name came up during the Enforcement Directorate's ongoing investigation into a money laundering case connected to the alleged liquor scam. Raids are currently underway at 14 locations across Chhattisgarh.



New Delhi. The Enforcement Directorate (ED) on Monday conducted raids at multiple locations linked to Chaitanya Baghel, the son of former Chhattisgarh Chief Minister and Congress leader Bhupesh Baghel, in connection with the state's alleged liquor scam. During the searches, the probe agency seized some electronic gadgets and documents. Chaitanya Baghel's name came up during the ED's ongoing investigation into a money laundering case connected to the scam. Raids are currently underway at 14 locations across Chhattisgarh at premises linked to the former Chief Minister's son and some other individuals connected to the case as well. Sources told India Today TV that Chaitanya Baghel could be summoned by the Enforcement Directorate for a first round of questioning today. According to a probe agency official, the ED has found that Chaitanya Baghel is also the recipient of proceeds of crime generated from the scam wherein the total proceeds amount to about Rs 2,161 crore, siphoned off via various schemes. "During the investigation, we have uncovered some evidence that links Chaitanya Baghel to the scam. Based on the existing evidence, we are conducting these searches," ED sources said. The ED investigation has uncovered a complex network allegedly involving senior bureaucrats, politicians, and officials from the Excise Department. This syndicate is accused of operating a "parallel" excise system, wherein unaccounted liquor was sold through government-run outlets without proper documentation, thereby diverting substantial revenue away from the state. The modus operandi purportedly included the use of duplicate holograms and bottles to facilitate the sale of illicit liquor. In July 2023, the ED filed a prosecution complaint, naming key individuals such as Anwar Dhebar, brother of Raipur Mayor Aijaz Dhebar; former IAS officer Anil Tuteja; and Arunpati Tripathi, Managing Director of the Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL). The agency alleged that these individuals played pivotal roles in orchestrating the scam, which involved manipulating procurement processes and accepting commissions from select liquor manufacturers. The ED's investigation revealed that the alleged corruption led to a loss of Rs 2,161 crore to the state exchequer. In response, the agency has attached properties worth approximately Rs 205.49 crore linked to various accused individuals, including businessmen and former bureaucrats. Bhupesh Baghel has previously denied allegations related to the scam, labelling the ED's actions as politically motivated.

After AI, IndiGo faces flak over failure to provide wheelchair aid to 83-year-old passenger

NEW DELHI. Days after an 82-year-old woman was reportedly injured at the Delhi Airport due to Air India's failure to provide a pre-booked wheelchair, another similar incident has surfaced – now involving IndiGo Airlines. IndiGo is facing backlash over its alleged failure to assist an 83-year-old passenger, Susama Rath, upon her arrival at the Delhi Airport. Rath, who was travelling from Bhubaneswar on IndiGo's 6E 5061 flight on March 5,



was allegedly left to navigate the airport by foot despite having pre-requested wheelchair assistance. Dr Bishnu Prasad Panigrahi, Group Head Medical Strategy & Operations at Fortis Healthcare and Rath's son-in-law, took to social media to express his outrage. He accused the airlines of negligence and insensitivity, flagging 'lack of concern for elderly passengers'. In response, IndiGo claimed that wheelchairs must be pre-booked at least 48 hours before departure. The airlines claimed no such request was reflected in Rath's booking but extended an apology for the inconvenience. "Dr Panigrahi, we'd like to extend our deepest gratitude for allowing us to address this on the call," it posted on X.

Massive jam in Ghazipur as protesters block National Highway after man shot dead

NEW DELHI. A massive traffic jam unfolded on National Highway 24 in East Delhi's Ghazipur area as protests erupted following the shooting death of a 32-year-old man on Monday. According to the Delhi Police, they received a medico-legal case (MLC) report from Lal Bahadur Shastri Hospital, stating that a man had suffered a gunshot wound on Sunday and was declared dead on arrival. The man, identified as Rohit Chawda, was a resident of Ghazipur village. Deputy Commissioner of Police (East) Abhishek



Dhanias, stated that further details are being verified and that efforts are underway to bring all culprits to justice. According to news agency ANI, the police have registered a case under the Arms Act and for murder. CCTV footage from near the crime scene is being reviewed to identify the attacker. Authorities are also working to determine the route the assailants used to arrive at the location and how they fled after committing the crime. Following the murder, local residents and supporters gathered in large numbers, blocking NH-24 to demand immediate justice. The highway remained jammed for hours, severely impacting traffic movement. According to the police, the murder was the result of an internal dispute related to money between Rohit and the accused. They confirmed that two individuals have been arrested in connection with the case and that multiple teams are actively investigating the matter.

Unused Covid-era medical equipment at Delhi's GTB hospital to be given to other states

NEW DELHI. Medical equipment purchased during the Covid-19 pandemic, including ventilators, oxygen concentrators, masks, and PPE kits that have remained unused for years in GTB Hospital's warehouse will now be distributed to hospitals across Delhi and other states. The Health Department has issued advisory outlining guidelines for their use and redistribution to central hospitals, city-run health institutes, and other states' hospitals. The decision comes after Chief Minister Rekha Gupta's surprise visit to GTB Hospital, where she expressed concern over the stockpiled yet unutilised medical equipment. During her inspection, she discovered that several



critical and expensive medical devices were lying unattended in hospital warehouses without proper supervision. Expressing displeasure over the negligence, the CM directed

hospital authorities to immediately ensure better utilization of these resources. Following her orders, the Health Department has issued corrective measures and instructed all government hospitals to properly store equipment per safety norms. Technical experts will inspect the machines, assess their condition, and make them functional for future use. Hospitals have also been directed to redistribute surplus equipment to other state and central hospitals in Delhi, while reaching out to other states that might require such resources. Hospitals must prioritise using existing stock before purchasing new equipment to prevent unnecessary expenditure.

Weather may dampen Holi celebrations in Delhi as rain predicted on March 14

NEW DELHI. A shift in weather patterns is expected to add an unpredictable twist to this year's Holi celebrations, with the India Meteorological Department (IMD) predicting light rainfall in Delhi and other parts of the country on March 14. According to weather department forecast, the country has experienced dry weather over the past few days, but significant changes are anticipated, beginning with the arrival of a western disturbance over the Himalayas on Sunday. Typically active during winter, the western disturbance has remained influential into March this year. A strong system at the end of February and early March brought heavy snowfall to the mountains and widespread rainfall in the plains. Another such system is set to become active over the upper Himalayan region on Sunday, triggering fresh snowfall. IMD has also predicted that the impact of the western disturbance will not be



limited to mountainous regions. Between March 9 and 14, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Uttarakhand are expected to experience snowfall in various areas. Rainfall is predicted in Punjab from March 12 to 14, while Haryana and Delhi could see showers on March 13 and 14. Western Uttar Pradesh may also receive rainfall on March 14, coinciding with Holi celebrations. Delhi's maximum temperature settled 4.4 notches above normal at 32.8

degrees Celsius on Sunday. For Monday, the weather office has forecast misty conditions, with the maximum and minimum temperatures expected to settle at 32 degrees and 15 degrees Celsius. Strong winds are also expected to sweep through Delhi and its neighbouring areas on March 11 and 12, reaching speeds of up to 30 km per hour across the Indo-Gangetic plains. Meanwhile, heatwave conditions are likely in parts of Gujarat, including Saurashtra and Kutch, in the days leading up to Holi. Gujarat usually sees a rise in temperature after Holi, but this year, the Meteorological Department has issued a pre-Holi yellow alert. The alert, covering 13 districts, is in effect for four days starting today, with intense heat expected over the next 48 hours. Rising temperatures are also expected to affect Goa and the Konkan region, intensifying heat stress in these areas.

Vanuatu moves to cancel fugitive Lalit Modi's passport: Bid to avoid extradition

Vanuatu Prime Minister Jotham Napat accused the fugitive businessman and ex-IPL chief Lalit Modi of using the island nation's citizenship to evade extradition.

New Delhi. Fugitive businessman and Indian Premier League (IPL) founder Lalit Modi has lost the citizenship of the island nation Vanuatu, which he had reportedly acquired before recently applying to surrender his Indian passport at the Indian High Commission in London. Vanuatu Prime Minister Jotham Napat on Monday ordered the

Citizenship Commission to cancel Modi's Vanuatu passport, accusing the fugitive businessman of using the South Pacific Island nation's citizenship to evade extradition. Lalit Modi, who is believed to be living in London, is wanted by Indian law enforcement agencies in connection with allegations that he was involved in embezzlement of crores of rupees during his stint as the boss of the IPL. "I have instructed the Citizenship Commission to immediately begin proceedings to cancel Lalit Modi's Vanuatu passport," Vanuatu's PM Napat said in an official statement. The prime minister also explained that Modi's citizenship application had undergone standard background checks, it was only in the past 24 hours that the country came across information that Interpol had twice rejected India's requests to issue an alert



notice against him due to insufficient judicial evidence. Such an alert, if approved, would have automatically led to the rejection of the businessman's citizenship application. "I have been made aware in the past 24 hours that Interpol twice rejected Indian authorities' requests to issue an alert notice on Mr Lalit Modi due to lack of substantive judicial evidence. Any such alert would have triggered an automatic rejection of Mr Modi's citizenship

application," the statement read. Furthermore, PM Napat also pointed out that Vanuatu citizenship is a privilege, not a right, and applicants must seek it for legitimate reasons. "None of those legitimate reasons include attempting to avoid extradition, which the recent facts brought to light clearly indicate was Lalit Modi's intention," he stated. The fugitive businessman submitted an application to surrender his Indian passport on March 7, a move later confirmed by the Ministry of External Affairs (MEA). "He has made an application for surrendering his passport in the high commission of India, London. The same will be examined in light of extant rules and procedures. We are also given to understand that he has acquired citizenship of Vanuatu. We continue to pursue the case against him as required under law" MEA spokesperson Randhir Jaiswal had said.

NEWS BOX

Trump says US in talks with four groups over TikTok sale: All options good

world. US President Donald Trump said on Sunday that his administration was in touch with four different groups about the sale of Chinese-owned social media platform TikTok, and that all options were good.

TikTok's fate has been up in the air since a law requiring its owner ByteDance to either sell it on national security grounds or face a ban took effect on January 19. Trump, after taking office on January 20, signed an executive order seeking to delay by 75 days the enforcement of the law.As asked if there was going to soon be a deal on TikTok, Trump told reporters aboard the Air Force One, "it could." "We're dealing with four different groups, and a lot of people want it ... all four are good," he added.

TikTok and ByteDance did not immediately respond to Reuters' requests for comment outside of normal business hours.The turmoil at TikTok has attracted several potential buyers, including former Los Angeles Dodgers owner Frank McCourt, who have expressed interest in the fast-growing business analysts estimate could be worth as much as \$50 billion.

Donald Trump declines to rule out 2025 US recession

WASHINGTON. President Donald Trump declined Sunday to rule out the possibility that the United States might enter a recession this year.

"I hate to predict things like that," he told a Fox News interviewer when asked directly about a possible recession in 2025."There is a period of transition, because what we're doing is very big -- we're bringing wealth back to America," he said, adding, "It takes a little time."Trump's commerce secretary, Howard Lutnick, was more definitive when asked Sunday about the possibility of a recession."Absolutely not," he told NBC's "Meet the Press" when asked whether Americans should brace for a downturn.

Trump's on-again, off-again tariff threats against Canada, Mexico, China and others have left the US financial markets in turmoil and consumers unsure what the year might bring.Stock markets just ended their worst week since the November election.

Measures of consumer confidence are down, as shoppers -- already battered by years of inflation -- brace for the higher prices that tariffs can bring.

And widespread government layoffs being engineered by Trump's billionaire advisor Elon Musk add further concern.When asked later Sunday to clarify his remarks on whether there could be a recession, Trump told reports on Air Force One "Who knows?"

Overall, the signs are mixed.

A widely watched Atlanta Federal Reserve index now predicts a 2.4 percent contraction of real GDP growth in the year's first quarter, which would be the worst result since the height of the Covid-19 pandemic.

Much of the uncertainty stems from Trump's shifting tariff policy -- effective dates have changed, as have the sectors being targeted -- as businesses and investors try to puzzle out what will come next.

Kevin Hassett, Trump's chief economic advisor, was asked on ABC whether tariffs were primarily temporary or might become permanent.Hassett said that depended on the behavior of the countries targeted. If they failed to respond positively, he said, the result could be a "new equilibrium" of continuing tariffs.

First Solar Eclipse Of 2025 This Month, Will It Be Visible From India

world. The first solar eclipse of the year is set to occur on March 29. The celestial event takes place when the Moon is closer to Earth and passes directly between the Earth and the Sun, blocking sunlight and casting a shadow on Earth's surface. It will be a partial solar eclipse, covering only a portion of the Sun.

On March 29, the solar eclipse will begin at 2:20 pm (IST) and end at 6:13 pm, lasting approximately four hours. The eclipse will be at its peak at 04:17 pm, reported NASA.

The solar eclipse will be visible from Asia, Africa, Europe, the Atlantic Ocean, the Arctic Ocean, North America, and South America. Unfortunately, it will not be visible from India.Unlike a lunar eclipse, which can be safely observed with the naked eye, a solar eclipse should not be watched directly. It can result in retinal burns and irreversible eye damage. Wearing



appropriate eye protection is always advised when observing a solar eclipse.NASA has predicted two solar eclipses for 2025. The first is scheduled for March 29, while the second is likely to take place on September 21.

This year, there will also be two lunar eclipses. The first one will occur on March 14, coinciding with the festival of Holi. It will begin at 09:29 am and end at 03:39 pm. The event will last for an hour and four minutes. The eclipse will reach its peak at 12:29 PM. The celestial event will not be visible from India.

It will be a "Blood Moon", which occurs when the Earth passes directly in front of the Sun and Moon, giving the moon a red appearance. This happens when the Earth's atmosphere bends some sunlight towards the Moon, absorbing all the other colours.

Israel cuts Gaza's power, hitting water supply; Hamas calls it starvation policy

UN criticises Israel for suspending supplies to Gaza

Hamas calls it part of Israel's 'starvation policy'

US confirms direct talks with Hamas for potential truce

Tel Aviv. Israel cut off the electricity supply to Gaza, officials said Sunday, affecting a desalination plant producing drinking water for part of the arid territory. Hamas called it part of Israel's "starvation policy."

Israel last week suspended supplies of goods to the territory of more than 2 million Palestinians, an echo of the siege it imposed in the earliest days of the war.Israel is pressing the militant group to accept an extension of the first phase of

their ceasefire. That phase ended last weekend. Israel wants Hamas to release half of the remaining hostages in return for a promise to negotiate a lasting truce.Hamas instead wants to start negotiations on the ceasefire's more difficult second phase, which would see the release of remaining hostages from Gaza, the withdrawal of Israeli forces and a lasting peace. Hamas is believed to have 24 living hostages and the bodies of 35 others.

The militant group which has warned that discontinuing supplies would affect the hostages said Sunday that it wrapped up the latest round of ceasefire talks with Egyptian mediators without changes to its position.Israel has said it would send a delegation to Qatar on Monday in an effort to "advance" the negotiations.Israel had warned when it stopped all supplies that water and electricity could be next. The letter from Israel's energy minister to the Israel Electric Corporation tells it to stop



selling power to Gaza.The territory and its infrastructure have been largely devastated, and most facilities, including hospitals, now use generators. Hamas spokesman Hazem Qassam said that Israel has "practically" cut off electricity since the war began and called the latest decision part of Israel's "starvation policy, in clear disregard for all intenational laws and norms."

The desalination plant was providing 18,000 cubic meters of water per day for central

Gaza's Deir al-Balah area, according to Gisha, an Israeli organization dedicated to protecting Palestinians' right to freedom of movement. Executive director Tania Hary said that it's expected to run on generators and produce around 2,500 cubic meters per day, about the amount in an Olympic swimming pool.Israel's restrictions on fuel entering Gaza have a larger impact, Hary said, and water shortages are a looming issue, because fuel is needed for distribution trucks.Israel has faced sharp criticism over suspending supplies.

"Any denial of the entry of the necessities of life for civilians may amount to collective punishment," the UN human rights office said Friday.The International Criminal Court said there was reason to believe Israel had used "starvation as a method of warfare" when it issued an arrest warrant for Prime Minister Benjamin Netanyahu last year.

US authorities arrest Palestinian student protester at Columbia University

New York. Agents from US President Donald Trump's administration arrested a Palestinian graduate student who played a prominent role in last year's pro-Palestinian protests at New York's Columbia University, four fellow students said on Sunday.

The student, Mahmoud Khalil at the university's School of International and Public Affairs, was arrested by US Department of Homeland Security agents at his university residence on Saturday, said undergraduate student Maryam Alwan and three other students who asked not to be identified, citing fears of reprisals.Khalil has been one of the negotiators with school administrators on behalf of the pro-Palestinian student protesters, who set up a tent encampment on a Columbia lawn last year.Khalil's detention appears to be one of the first efforts by Trump, a Republican who returned to the White House in January, to fulfill his promise to seek the deportation of some foreign students involved in the pro-Palestinian protest movement. The October 7, 2023, Hamas attack on



Israel and subsequent Israeli assault on Gaza led to months of pro-Palestinian protests that roiled US college campuses.A spokesperson for Columbia said the school was barred by law from sharing information about individual students.Spokespeople for the Department of Homeland Security and the Department of State, which oversees the country's visa system, did not respond to questions.In an interview with Reuters a few hours before his arrest on Saturday, Khalil said he was concerned that he was being targeted by the government and some conservative pro-Israel groups for speaking to the media.

The Trump administration on Friday said

it had cancelled government contracts and grants awarded to Columbia University worth about \$400 million. The government said the cuts and the student deportation efforts are because of antisemitic harassment at and near Columbia's Manhattan campus."What more can Columbia do to appease Congress or the government now?" Khalil said before his arrest, noting that Columbia had twice called in police to arrest protesters and had disciplined many pro-Palestinian students and staff, suspending some.

"They basically silenced anyone supporting Palestine on campus and this was not enough. Clearly Trump is using the protesters as a scapegoat for his wider agenda fighting and attacking higher education and the Ivy League education system."Alwan, a Columbia senior who has protested alongside Khalil, said the Trump administration was dehumanising Palestinians."I am horrified for my dear friend Mahmoud, who is a legal resident, and I am horrified that this is only the beginning," she said.

Europe's Dependence On US Arms Rose In Last 5 Years: Report

Stockholm, Sweden.NATO countries in Europe more than doubled their arms imports in the past five years, more than 60 percent of which were purchases of US weaponry, researchers on Monday.

The findings by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) coincide with an announcement by European Union states that they intend to strengthen the continent's defence capabilities in response to a US foreign policy shift under President Donald Trump.

In the period 2020 to 2024, Ukraine became the world's largest arms importer.The United States consolidated its position as the world's top weapons exporter -- accounting for 43 percent of global exports -- far ahead of the second largest, France, which accounted for 9.6 percent.Over that same period, arms imports by European NATO members rose by 105 percent compared to the previous five years.That reflects "the rearmament taking place among states in Europe in response to the threat from Russia",

said Mathew George, the head of the SIPRI Arms Transfers Programme. The United States provided 64 percent of these weapons, compared to 52 percent in the period from 2015 to 2019.



"With an increasingly belligerent Russia and transatlantic relations under stress during the first Trump presidency, European NATO states have taken steps to reduce their dependence on arms imports and to strengthen the European arms industry," senior researcher Pieter Wezeman said. "But the transatlantic arms supply

relationship has deep roots. "Imports from the USA have risen and European NATO states have almost 500 combat aircraft and many other weapons still on order from the USA," he added.Countries including Italy and the United Kingdom have also bought US-made F35 fighter jets and Patriot anti-air defence systems, which are complex systems that are difficult to quickly substitute, Wezeman told AFP."The F-35 is, of course, an American product but as part of (F-35) sales to European states ... the industry in those states has also been involved in the production of key components," the researcher said.Countries like Belgium, the Netherlands and Denmark -- which is currently embroiled in diplomatic tensions with the United States over Greenland's future -- are even more dependent on US weaponry, he explained.

Changing that "would require an enormous financial and political investment", Wezeman said.



election results.Mark Carney's statement came as trade tensions between Ottawa and Washington remain high.In December, then-US President-elect Donald Trump referred to Canadian Prime Minister Justin Trudeau as the 'Governor' of the "Great State of Canada" while threatening to impose tariffs on Canadian products.On February 3, after taking office as US President, Trump suggested that Canada should become the 51st US state to avoid tariffs and receive military protection. Reports indicate that Canadian officials took his remarks seriously.Mark Carney also declared that Canada's countermeasures against Trump's tariff threats would persist until the US demonstrates a genuine commitment to free and fair trade."We cannot and will not let him succeed," Carney asserted. "We are Canada strong".Justin Trudeau's decision to step down in January after more than nine years in power, amid plummeting approval ratings, forced the ruling Liberal Party into a swift leadershiprace.

Mark Carney's victory marks a historic shift, making him the first political outsider to become Canada's Prime Minister.

North Korea unveils its first nuclear-powered submarine, with 'help' from Russia

—Moon, the submarine expert, said that North Korea may have received Russian technological assistance to build a nuclear reactor to be used in the submarine in return for supplying conventional weapons and troops to support Russia's war efforts against Ukraine.

Seoul. North Korea unveiled for the first time a nuclear-powered submarine under construction, a weapons system that can pose a major security threat to South Korea and the US.The state media agency on Saturday released photos showing what it called "a nuclear-powered strategic guided missile submarine," as it reported leader Kim Jong Un's visits to major shipyards where warships are built.The Korean Central News Agency, or KCNA, didn't provide details on the submarine, but said

that Kim was briefed on its construction.The naval vessel appears to be a 6,000-ton-class or 7,000-ton-class one which can carry about 10 missiles, said Moon Keun-sik, a South Korean submarine expert who teaches at Seoul's Hanyang University. He said that the use of the term "the strategic guided missiles" meant it would carry nuclear-capable weapons."It would be absolutely threatening to us and the US," Moon said.US National Security Council spokesman Brian Hughes said that "we're aware of these claims and do not have additional information to provide at this time." "The US is committed to the complete denuclearization of North Korea," Hughes said.A nuclear-powered submarine was among a long wish list of sophisticated weaponry that Kim vowed to introduce during a major political conference in 2021 to cope with what he called escalating US-led military threats. Other weapons were solid-fueled intercontinental ballistic missiles,

hypersonic weapons, spy satellites and multi-warhead missiles. North Korea has since performed a run of testing activities to acquire themNorth Korea obtaining a



greater ability to fire missiles from underwater is a worrying development, because it's difficult for its rivals to detect such launches in advance.Questions about how North Korea, a heavily sanctioned and impoverished country, could get resources and technology to build nuclear-powered

submarines have surfaced.Moon, the submarine expert, said that North Korea may have received Russian technological assistance to build a nuclear reactor to be used in the submarine in return for supplying conventional weapons and troops to support Russia's war efforts against Ukraine.He also said that North Korea could launch the submarine in one or two years to test its capability before its actual deployment.North Korea has an estimated 70-90 diesel-powered submarines in one of the world's largest fleets. However, they are mostly aging ones capable of launching only torpedoes and mines, not missiles..In 2023, North Korea said that it had launched what it called its first "tactical nuclear attack submarine," but foreign experts doubted the North's announcement and speculated that it was likely a diesel-powered submarine disclosed in 2019. Moon said that there has been no confirmation that it has been deployed.

Shahid Kapoor Reacts To Reuniting With Ex-Girlfriend Kareena Kapoor At IIFA: 'Totally Normal'

Shahid Kapoor and Kareena Kapoor reunited at the IIFA 2025 press conference, sharing a warm hug and smiles. Fans were thrilled, but Shahid downplayed it, saying their meetings are normal.



Recently, we got a blast from the past, and the internet is eating it up! Shahid Kapoor and Kareena Kapoor, once the It couple of B-town, had a sweet little reunion at the IIFA 2025 press conference, and let's just say—our nostalgia levels simply shot up. The ex-lovebirds were spotted sharing a warm hug, exchanging smiles, and having a quick chat while the paparazzi froze the moment for all of us to obsess over. And obsess we did! The rare sight of the former couple left fans in a frenzy. But before we could all get carried away, Shahid Kapoor reacted to it. Speaking on the green carpet of the IIFA Digital Awards, the Kabir Singh star was asked about the much-hyped reunion. His response was a casual shrug. "For us, it's nothing new... aaj stage pe mile aur hum log idhar udhar milte rehte hai (today we met on stage, but we keep running into each other here and there). It's totally normal for us... if people felt nice, it's nice." Once upon a time in the 2000s, Shahid Kapoor and Kareena Kapoor were Bollywood's beloved real-and-reel-life couple, setting screens on fire with their chemistry in films like Fida, Chup Chup Ke, and the cult classic Jab We Met. But just before Jab We Met wrapped, their love story took a different turn, and they decided to go their separate ways. Fast forward to today, both stars have built beautiful lives of their own. Kareena found her happily ever after with Saif Ali Khan, and the duo is now proud parents to two adorable boys. Meanwhile, Shahid, too, found love outside the film industry, marrying Mira Rajput, with whom he shares a son and a daughter. The 25th edition of IIFA is being held in Jaipur, Rajasthan.



Sikandar: Director Murugadoss confirms Salman Khan's film 'isn't a remake'

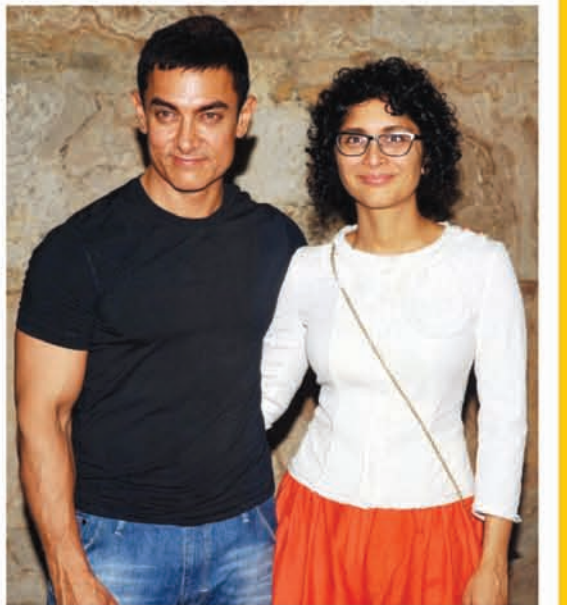
Sikandar director AR Murugadoss revealed how the film 'isn't a remake' and offers a unique story. The movie stars Salman Khan and Rashmika Mandanna in the lead.



Salman Khan's Sikandar is one of the highly anticipated films of 2025. Starring Salman Khan and Rashmika Mandanna alongside Salman, the film offers something entirely new to the audience. Director AR Murugadoss shared how the film is a 'completely original story' and not a remake. Director A.R. Murugadoss shared how the story is not a remake of any film and offers a fresh perspective. "This is a completely original story. Every scene and every frame of Sikandar has been designed and executed with authenticity, offering a fresh narrative and experience. It's not a remake or adaptation of any existing film. An essential part of the film's originality is its stunning background score, crafted by the immensely talented Santosh Narayanan. His music perfectly complements the film's energetic tone and vibrant visuals, adding an emotional depth that enhances every scene," he said. The film also reunites Salman with producer Sajid Nadiadwala, known for delivering blockbusters like Kick and Mujhse Shaadi Karogi. Sikandar releases in cinemas on Eid, March 28, 2025. Salman Khan last appeared in Tiger 3 alongside Katrina Kaif and Emraan Hashmi. He also has Siddharth Anand's Tiger vs Pathaan, where he will be once again sharing screen space with superstar and close friend Shah Rukh Khan.

Kiran Rao On Parents' Reaction To Her Marriage With Aamir Khan: "They Thought I Might Be Overshadowed By Him"

Kiran Rao, an Indian film producer and director, was married to Bollywood superstar Aamir Khan for over 15 years



Filmmaker Kiran Rao recently opened up about her marriage to Aamir Khan. When asked about her parents' reaction to her decision to marry the actor, Kiran told ANI, "It was a shocker for them. "They were taken aback. In their eyes, I had a lot of promise. I was someone who wanted to do a lot of things, and they were worried that I might be overshadowed by Aamir's larger-than-life persona," she added. Given Aamir's immense fame, Kiran did feel the pressure of living in his shadow. However, what brought her comfort was Aamir's unwavering support for her individuality. "Aamir has never expected me to be a certain way. He has always been happy for me to be myself, and that's one of the greatest things about him," she shared. "Aamir and I will always be there for each other," she concluded. Kiran Rao, an Indian film producer and director, was married to Bollywood superstar Aamir Khan for over 15 years. They married in 2005 and welcomed their son, Azad Rao Khan, in 2011. However, in July 2021, they announced their separation.

Radhika Apte to make her directorial debut with action-fantasy film Kotya

Acclaimed actor Radhika Apte will soon be making her directorial debut with the action-fantasy film, Kotya. The announcement was made as a part of the CineV-CHD Market lineup.



Actor Radhika Apte is all set to make her directorial debut with the action-fantasy film, Kotya. The announcement was disclosed during the CineV-CHD Market lineup. The said lineup also features at least 22 projects by a diverse group of filmmakers. Variety reported that Kotya is a "Hindi/Marathi action-fantasy following a young migrant sugarcane cutter who gains superpowers after a forced medical procedure and uses them to free her family from debt." It will reportedly be bankrolled by filmmaker Vikramaditya Motwane. Radhika Apte is known for her work in films such as PadMan, Andhadhun, Vikram Vedha, A Call to Spy, Kabali, and Lust Stories, among others. She was last seen in the BAFTA-nominated film, Sister Midnight. Sister Midnight had earlier premiered at the Cannes Film Festival and bagged a BAFTA nomination in the Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer category. Besides her many professional achievements, Apte has much to celebrate on the personal front. The actor recently welcomed a baby with husband Benedict Taylor. The actor had shared the happy news on her social media handle, where she was seen breastfeeding the child.

